04 - दलित राजनीति की जंग में आमने-सामने मायावती व चंद्रशेखर

05 - वैवाहिक पवित्रता और रिश्तों के अंतहीन अपराध

A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 15 जुलाई, 2026

06 - एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जिले में...

07 - सिविल कांट्रेक्टर का ड्राइवर ही निकला चोर

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 313, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

अवकाश के बीच भी
हम दोनों उतना ही साथ होंगे
जितना अवकाश के बिना..!
साथ होंगी स्मृतियां
अवकाश के बिना भी
विस्मृति कैसे होगी भला स्मृति के बिना..
जीवन कभी छुट्टी नहीं लेगा
कोई वीक एंड नहीं होगा समय का
एक काश हमारे साथ-साथ चलता रहेगा
जैसे साथ चलती है स्मृति..
विस्मृति की परछाई लिए
आजीवन..!

- सारंग उपाध्याय

प्रसंगवश

मंदिरों की पूँजीवादी व्यवस्था आखिर किसके हित में है?

डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला

भारत और भारत के बाहर जितने भी देव-प्रतिष्ठान हैं, वे हिन्दू धर्म के प्रचार-केन्द्र नहीं है। वे हमारे आत्मविश्वास को जाग्रत करने वाले ऊर्जा के स्रोत की तरह विकसित किये गये हैं। मंदिरों के स्थापत्य का वैभव अलग बात है, लेकिन उनकी भीतरी ऊर्जा ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। हिन्दू मंदिरों के खड़े होने का ढंग उनकी आंतरिक शक्ति को भी जाहिर करता है। उन्हीं मंदिरों का प्राण-तत्व प्रबल माना जाता है, जहाँ श्रद्धालुओं का सतत आना-जाना है।

पिछले कुछ वर्षों में मंदिरों की प्रसिद्धि का लाभ उठाकर जो वर्ग सबसे पहले आगे आया, वह व्यापारियों का वर्ग था। कहीं भी जाइए, मंदिरों के आसपास दूर-दूर तक व्यापार फैला हुआ है। इस व्यापार ने मंदिरों की व्यवस्था को भी बाजार से जोड़ने का काम किया। मंदिर में प्रवेश से पहले ही दर्शनार्थी चकाचौंध वाले मेले में उलझा दिये जाते हैं। भगवान् से मिलने की फीस तय होने लगी है, पूजा करने के लिये रसीद कटने लगी है, प्रसाद तक बिकने लगे हैं।

आजकल मंदिरों की महिमा इस बात से आँकी जाने लगी है कि वहाँ के सालाना नगदी चढ़ावे का आँकड़ा कितना बड़ा है। टीवी चैनलों पर नोटों की गणना वाले कक्ष के वीडियो वायरल कर यह बताने की कोशिश की जाती है कि अमुक मंदिर के भगवान कितने मालामाल हैं। चढ़ावे की खबरें अखबारों के मुखपृष्ठ पर छपती हैं। यदि ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, तो मंदिर की प्रबंध समिति की चिन्ता बढ़ जाती है। वह फौरन ट्रस्टियों की बैठक बुला लेती है। यह वैसे ही होता है, जैसे बड़े व्यापारी अपने व्यवसाय में मंदी आने पर प्रायः करते हैं।

पहले की तुलना में आज मंदिरों की आय में चौंका देने वाली वृद्धि दिखाई देती है। मंदिरों का रख-रखाव और विकास इस तरह किया जाने लगा है कि वह श्रद्धालुओं के लिये आकर्षण का केन्द्र भी बने, और पर्यटन के व्यवसाय को भी लाभ देने वाला हो। मंदिर में कोई भी दर्शनार्थी खाली हाथ तो जाता नहीं। गरीब से गरीब भी वहाँ जाकर सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिये आतुर लगता है। अमीर भी अपनी आय का एक नियत हिस्सा मंदिर में चढ़ाकर ही हल्का होता है। इसीलिये आजकल मंदिर आलीशान हैं, वहाँ की व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद हैं। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि मंदिरों की पूंजीवादी व्यवस्था आखिर किसके हित में है?

मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, उसका एक हिस्सा मंदिर की व्यवस्था के लिये सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानवता की सेवा में खर्च कर भगवान् के धन का अच्छा उपयोग किया सकता है। 'मानव-सेवा ही माधव-सेवा है', यह वाक्य केवल सुनने-सुनाने के लिये नहीं, हममें चरितार्थ भी होते रहना चाहिए। भगवान के धन-सम्पन्न मंदिरों के रहते यदि मानवता दुःखी है, लाचार है, तो यह चिन्ता का विषय है। भगवान् दीनबन्धु हैं, दीनदयालु हैं, तो उनका चढ़ावा दीन-हीन लोगों की सहायता के लिये काम में आए, तो किसे आपत्ति होगी? जो मंदिर धनाढ्य है, वहाँ के प्रशासन को इस पहलू पर प्राथमिकता से विचार कर निर्णय लेने का वक्त आ गया है। दलितों, पिछड़े हुओं, दिव्यांगों, मंदिर के बाहर लाइन लगाये हुए भिखारियों, शोषितों, सुविधा-वंचितों और निराश्रितों के लिये नियमित रोजगार का निर्माण कर हमारे मंदिर राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। हिन्दू-धर्म और राष्ट्र-धर्म को आपस में मिलते हुए देखने की सच्ची अभिलाषा हो, तो इस दिशा में पहल करने का यही मौका है। मंदिरों के जिम्मेदार ठान लें, तो यह काम बिल्कुल भी कठिन नहीं।

क्या मंदिरों की भारी-भरकम आमदनी से ऐसे अस्पताल नहीं खोले जा सकते, जहाँ गरीबों की असाध्य बीमारियों का मुफ्त इलाज हो सके। क्या ऐसा नहीं हो सकता, कि वनांचलों में रहने वाले निर्धन बच्चों के लिये गुरुकुल चलाये जाएँ। क्या यह भगवान् के मंदिरों की सोच का विषय नहीं कि वह सुविधावंचित बच्चों और स्त्रियों के आत्म-सम्मान के लिये अपना कोश खोल दें। क्या हमारे मंदिर अपने धन-वैभव से वृद्धाश्रमों के प्रचलित ढांचे को सच्चे सेवाश्रम में नहीं बदल सकते? क्या बेघर लोगों को मंदिर की जमा पूँजी से आसरा नहीं मिल सकता?

मंदिरों को होने वाली करोड़ों की आय आखिर जाती कहाँ है? अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर या शिर्डी के साईं मंदिर की आय का पूरा हिस्सा मंदिर के विस्तार और सुविधाओं पर ही खर्च होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर,तिरुपति बालाजी मंदिर, वैष्णोदेवी और दूसरे कई प्रसिद्ध मंदिरों की आय का कुछ हिस्सा मंदिरों के विकास के नाम पर, और कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में चला जाता है। यह पूँजीवादी व्यवस्था है, जो समाज-सेवा और परोपकार से अब भी बहुत दूर है।

मंदिर के व्यवस्थापकों को आगे आना होगा। मंदिर कुछ सम्पन्न धनिकों के लिये धन उगाते रहने वाले संस्थान के रूप में न पहचाने जाने लगे, इसके लिये उच्च स्तर पर व्यापक योजना तैयार कर उसे लागू करना जरूरी है। मंदिरों का पवित्र धन उन पवित्र कार्यों में लगे, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिलता हो। गरीबों के स्वास्थ्य और शिक्षा का दायित्व मंदिर के ट्रस्ट सम्हाल लें, तो यह सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण होगा। हिन्दुत्व की रक्षा के लिये इससे बेहतर क्या हो सकता है।

मंदिर हमारे हृदय खोलने के लिये हैं, हमारे भीतर के सुप्त देवांशों को जगाने के लिये हैं। देव-दर्शन से हमारे पाप ही नष्ट नहीं होते, हममें विश्व-कल्याण की ऊर्जा भी आती है। 'धर्म की जय' और 'अधर्म का नाश' तभी होगा, जब समाज के सबसे निचले व्यक्ति को उत्साह और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्राणवायु मिलेगी। समाज सुधार की नई बयार अब बड़े-बड़े मंदिरों से चलनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ, तो 'सं वो मनांसि जानताम्' वाली वैदिक ऋषि की वाणी सचमुच जी उठेगी।

(लेखक संस्कृत के विद्वान, लेखक और शिक्षाविद् हैं)

सीएम मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

टेक होम राशन की जिम्मेदारी अब संभालेगा महिला एवं बाल विकास

- प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण के लिए 10 हजार 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- शहरों के लिए बड़ी राशि को मिली मंजूरी ● कैबिनेट की अगली मीटिंग जगदीशपुर में होगी

भोपाल (नप्र)। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है। कैबिनेट में प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले हुए हैं। एमपी कैबिनेट ने जन-कल्याण के लिए कुल 10 हजार 800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। साथ ही शहरों के कायाकल्प के लिए 8445 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मूंग उपार्जन के लिए भी सरकार ने राशि की मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण के लिए 10 हजार 800 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने शहरों के कायाकल्प के लिए नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8 हजार 445 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कुण्डलिया परियोजना को निरंतर रखने जैसे कई दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगायी है।

कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना- कैबिनेट ने राजगढ़ में जल संसाधन विभाग की कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। राजगढ़ जिले में निर्मित यह एक वृहद सिंचाई परियोजना है।

मूंग उपार्जन के लिए राशि मंजूरी- कैबिनेट ने रबी वर्ष 2023-24 विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत लक्ष्य से अधिक उपार्जित मूंग के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है।

वहीं, कैबिनेट ने टेक होम राशन की जिम्मेदारी आजीविका मिशन से वापस ले ली है। इसे महिला एवं बाल विभाग को दे दिया है। तात्कालिक रूप से अंतरिम व्यवस्था के रूप में स्व सहायता समूह से पूरक पोषण आहार प्रदाय के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश जारी होने के बाद विभाग स्थायी व्यवस्था स्थापित करेगा।

कार ने बाइक को टक्कर मारी, तीन दोस्तों की मौत

हरदा में घर लौटते समय फोरलेन पर हादसा

हरदा (नप्र)। हरदा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 12 बजे सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई। यह दुर्घटना डगावानीमा गांव के पास फोरलेन पर हुई। तीनों युवक एसी सुधारने का काम करते थे और काम खत्म कर घर लौट रहे थे। पुलिस ने मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सिटी कोतवाली थाना टीआई रोशनलाल भारती ने बताया कि तीनों युवक हरदा की ओर आ रहे थे। डगावानीमा से हरदा जाने वाले मार्ग पर फोरलेन पार करते समय बैतूल की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे में इनकी हुई मौत- संदीप पिता प्रकाश खरबड़े (30) निवासी किसानी मोहल्ला, सिराली वार्ड 2। संदीप अपने दो भाइयों में बड़े थे और उनका एक दो साल का बेटा है। सुनील पिता उमराव सिंह (30) निवासी सन्यासा, वर्तमान निवास बीबी सिटी कॉलोनी, हरदा। उनकी शादी तीन साल पहले हुई थी और उनका कोई बच्चा नहीं था। सुनील को उनके मामा ने पाला था और वह अपनी मां व पत्नी के साथ हरदा में रहते थे। गोपाल पिता धनसिंह राजपूत (31) निवासी ग्राम सोताड़ा थे। वह भी अपने दो भाइयों में बड़े थे और उनका तीन महीने का एक बेटा है।

● आगरा में विदेशी महिला पर्यटक की साड़ी खुली

महिला सिपाही ने साड़ी बांधी, अर्जेंटीना की टूरिस्ट ने कहा- थैंक्यू, यूपी पुलिस

आगरा (एजेंसी)। आगरा में साड़ी पहनकर ताजमहल देखने पहुंची अर्जेंटीना की महिला टूरिस्ट की साड़ी खुल गई। वह बार-बार साड़ी बांध रही थीं। मगर साड़ी खुल जा रही थी। इससे टूरिस्ट थोड़ा असहज हो गई। यह देख सुरक्षा में तैनात महिला सिपाही ने साड़ी बांधी। यह देख टूरिस्ट बहुत खुश हुई और उससे साड़ी बांधने और प्लेट्स बनाने का तरीका पूछा।

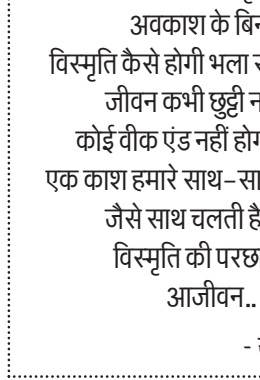

सिपाही ने उसे साड़ी पहनना सिखाया। इसके बाद टूरिस्ट ने उनसे हाथ मिलाया और थैंक्यू यूपी पुलिस बोला। इसके बाद महिला सिपाही के साथ फोटो खिंचवाई। टूरिस्ट ने कहा-मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। इंडिया की यह वंडरफुल ड्रेस है। मामला मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे ताजमहल के पश्चिमी गेट का है। अर्जेंटीना के मैसी शहर से टूरिस्टों का एक दल पश्चिमी गेट से ताजमहल पहुंचा। ग्रुप में एक महिला टूरिस्ट ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी। सभी अंदर ताजमहल में घूम रहे थे। चलने के दौरान महिला टूरिस्ट की साड़ी बार-बार खुल जा रही थी।तभी वहां क्विक रिस्पांस टीम में नियुक्त थाना ताज सुरक्षा पुलिस की महिला आरक्षी गुड्डी देवी उनके पास पहुंचीं। इसके बाद गुड्डी ने महिला टूरिस्ट को साड़ी पहनाई और उनकी प्लेट्स बनाई।विदेशी पर्यटक को साड़ी पहनने के बारे में बताया। सिपाही ने उन्हें बताया कि किस तरह साड़ी पहनी जाती है, जिससे पैरों में साड़ी न आए। विदेशी पर्यटकों ने गुड्?डी से पूछा कि वो कब साड़ी पहनती हैं? कैसे संभालती हैं?

● धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

परिसर के पास होगी हर शुक्रवार नमाज

मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दें, एएसआई परिसर से छेड़छाड़ न करें

नईदिल्ली/धार(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को धार भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए कोई खुला स्थान देने को कहा है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए यह जगह दी जाए।

अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) बिना कोर्ट की मंजूरी परिसर में किसी भी तरह का बदलाव न करे। सुप्रीम कोर्ट एमपी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें परिसर को मंदिर करार दिया गया है। सुनवाई के बाद भोजशाला संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भोजशाला में नियमित पूजा-अर्चना जारी रहेगी।

- **ज्ञानवापी मामला: मध्यस्थता कोर्ट में सुनवाई पूरी, दोनों पक्षों ने समझौता से किया इनकार**

ज्ञानवापी मामले में मध्यस्थता कोर्ट में सुनवाई आज (यानि मंगलवार) को पूरी हो गई। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। चार पत्रावलियों पर ये बातचीत हुई है। चारों पत्रावलियों के पक्षकार आए थे और सभी ने इस मामले में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता से इनकार किया और कोर्ट के निर्णय को सर्वमान्य मानने की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट का 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह पॉलिसी मौजूदा 2026-27 सत्र से लागू कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी।

दिव्यांगों पर टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना समेत 5 पर जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली

ठक्कर, निशांत जगदीश तंवर पर 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने दिव्यांगों पर विवादित टिप्पणी के केस में यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा- हमें लगता है कि रैना ने अदालत को गुमराह किया और हमारे आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया। हम उन पर जुर्माना लगाते हैं, जिसे 2 हफ्ते में जमा करना होगा।

- **कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया-** सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर मुस्लिम पक्षों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर माना गया था और परिसर में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
- **भोजशाला परिसर में कोई भी संरचनात्मक बदलाव नहीं होगा-** मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की मांग स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में कोई भी संरचनात्मक बदलाव नहीं करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि मामले की अंतिम सुनवाई करीब तीन सप्ताह बाद की जाएगी।

कांग्रेस प्रधान पद से इस्तीफा दे सकते हैं राजा वड़िंग

दिल्ली में राहुल गांधी की खड़गे से मीटिंग

लुधियाना/चंडीगढ़/नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई मीटिंग के बीच से सोर्सेज से ये खबर सामने आ रही है। दरअसल, पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की रिपोर्ट में ये साफ नजर आया है कि पूर्व सीएम व सांसद चरणजीत चन्नी और सांसद सुखजिंदर रंधावा किसी भी कीमत में राजा वड़िंग की अगुआई में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। रंधावा तो उन्हें इशारों में कंप्रोमाइज्ड लीडर तक बता चुके हैं।

अंतिम फैसला राहुल गांधी का- राहुल गांधी पर अब सारी बात टिकी हुई है। वह राजा वड़िंग को कुर्सी से हटाएंगे या फिर चन्नी से पीछा छुड़ाएंगे।

इससे पहले केरल में ज्यादातर विधायक केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे लेकिन जनता की भावना वीडी सतीशन के साथ थी।

तब राहुल गांधी ने ही वेणुगोपाल को समझाकर सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया। माना जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही बागी नेताओं से वन टु वन मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ही वड़िंग के इस्तीफे या फिर दूसरी कार्रवाई पर कोई फैसला हो सकता है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

2

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 15 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

ईरानी हमले में भारतीय की मौत

● ईरान ने किए तेल टैंकरों पर हमले, अमेरिका की ईरान पर 5 घंटे बमबारी ● भारत बोला- होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद हो, भारत आ रहे 11 जहाज अटके

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी/नईदिल्ली (एजेंसी)। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में सोमवार देर रात यूएई के दो तेल टैंकरों एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों जहाजों में 46 क्रू मेंबर्स थे जिसमें कुल 30 भारतीय थे। भारत आ रहे 11 जहाज अटक गए हैं।

मंत्रालय के मुताबिक एमटी अल बहियाह पर सवार 12 भारतीयों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। वहीं, एमटी मोम्बासा पर मौजूद 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है।भारत ने मंगलवार सुबह ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत ईरानी डिप्लोमेट्स को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने घटना पर गंभीर चिंता जताई और ईरानी मिशन से जवाब मांगा।

अमेरिका-जर्मनी-फ्रांस की राह पर भारत

सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

शिक्षा में करने जा रहा ऐतिहासिक बदलाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में सेक्स एजुकेशन को लेकर लंबे समय से चली आ रही झिझक या मनाही आखिरकार खत्म होने वाली है, क्योंकि यह विषय स्कूल के सिलेबस का औपचारिक हिस्सा बनने जा रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह एक कमिटी की सिफारिश के अनुसार स्कूलों/कॉलेजों में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन शुरू करने के लिए सहमत है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी- केंद्र सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 26 सदस्यों वाली एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इसका काम आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने वाले किशोरों की निजता के अधिकार से जुड़े मुद्दों की जांच करना था, खासकर POCSO एक्ट के संदर्भ में। पैनल के सदस्य- जिनमें टीआईएसएस TISS के विशेषज्ञ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, एनसीपीसीआर और एनएलएसए के प्रतिनिधि शामिल थे।

स्कूलों में जल्द शुरू होगी 'सेक्स एजुकेशन' - जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच के सामने पेश होते हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार ने कमिटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के पालन में दाखिल की गई है जिसमें नाबालिगों के गर्भवती होने और किशोरों के आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों के मामलों को POCSO एक्ट के तहत अपराध मानने से रोकने के तरीकों पर विचार करने को कहा गया था।

मुख्य सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए : पैनल

इसमें कहा गया कि किशोर शिक्षा के मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा की जा सकती है और उनमें सुधार किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों में सुरक्षा और बचाव की चिंताओं के साथ-साथ उम्र के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन के पहलुओं के बारे में जागरूकता को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाए ताकि एनईपी के समग्र विकास, आलोचनात्मक सोच और लाइफ स्किल विकसित करने के मुख्य सिद्धांतों को पूरा किया जा सके।

संक्षिप्त समाचार

महिला आरक्षण पर मोदी सरकार को विपक्ष की नेता का साथ

● पूर्व एमपी प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- समय आ चुका है

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई, 2026 से शुरू हो रहा है। संभावना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसमें एक बार फिर से महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित करने और परिसीमन के लिए संविधान संशोधन बिल लाने की कोशिश करेगी। विपक्षी इंडिया ब्लॉक की नेता और पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सभी दलों से अपील की है कि अब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को वास्तविक बनाने का समय आ गया है। शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व राज्यसभा सांसद इन दिनों एक्स के माध्यम से राजनीतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और कई बार पार्टी लाइन से अलग हटकर स्वतंत्र विचार रखती नजर आई हैं।

महाराष्ट्र में मिलावटी दूध का काला कारोबार, लोग पी गए 2.3 करोड़ लीटर नकली दूध

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में नकली दूध के बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। जांच में सामने आया है कि पिछले कई महीनों से डिटरजेंट पाउडर सहित अन्य रासायनिक पदार्थों से तैयार नकली दूध को असली दूध में मिलाकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में बेचा जा रहा था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की प्रारंभिक जांच के अनुसार पिछले कुछ महीनों में करीब 2.3 करोड़ लीटर मिलावटी दूध बाजार में खपाया जा चुका है।

एफडीए अधिकारियों के अनुसार मिलावट करने वाले गिरोह का तरीका बेहद सुनियोजित था। आरोपी प्रत्येक 100 लीटर दूध में लगभग 10 लीटर नकली दूध मिलाते थे। इसके बाद इस मिश्रित दूध को सामान्य दूध के रूप में विभिन्न डेयरियों और वितरण नेटवर्क के माध्यम से बाजार में भेज दिया जाता था।

यूपी गवर्नर पटेल बोलीं- 13 साल की बेटियों को बचाइए

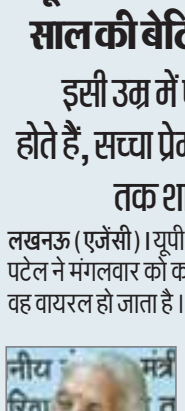

इसी उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं, सच्चा प्रेम तो पढ़ाई पूरी होने तक शादी से बचो

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को कहा- मैं कुछ कहती हूं तो वह वायरल हो जाता है। मेरे कहने का उद्देश्य गलत नहीं होता है। आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना मेरा मकसद है। 13 साल की बेटियों को बचाइए, उन्हें ध्यान दीजिए। इसी उम्र में मेंसुरेशन (पीरियड्स) शुरू होता है। इस उम्र की बेटियों की जांच जरूर होनी चाहिए। उन्हें समय से इलाज मिले। राज्यपाल लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 30वें दीक्षांत समारोह में बोल रही थीं। उन्होंने कहा, 13 साल की उम्र में आकर्षण होता है। एक-दूसरे से प्रेम होता है। जब एक-दो साल प्रेम के बाद पकड़ा जाता है तो वह सरकार के माथे आता है। टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो उन्हें ध्यान नहीं रहता कि क्लास में किसकी नजर किस पर है?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें 200 से बढ़कर 250 तथा रतलाम मेडिकल कॉलेज में 180 से बढ़कर 200 हुईं

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देशभर में स्वास्थ्य अधोसंरचना और चिकित्सा शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। आयुष्मान भारत, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मेडिकल सीटों में निरंतर वृद्धि, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार सशक्त हो रही है। बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें 200 से बढ़कर 250 तथा रतलाम मेडिकल कॉलेज में 180 से बढ़कर 200 होने से अधिक विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा और भविष्य में प्रदेश को अधिक दक्ष चिकित्सक उपलब्ध होंगे, जिससे आमजन को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने इस उपलब्धि के लिए दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं, फैकल्टी, चिकित्सकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनके समन्वित प्रयासों से यह सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, फैकल्टी की उपलब्धता, अस्पतालों के उन्नयन तथा मेडिकल सीटों में निरंतर वृद्धि के माध्यम से मध्यप्रदेश भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्त स्वास्थ्य तंत्र विकसित कर रहा है।

ट्विशा केस

गिरिबाला-समर्थ का फिर वॉयस सैंपल देने से इनकार

भोपाल (एजेंसी)। भोपाल में एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में मंगलवार को जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। सीबीआई ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों ने वॉयस सैंपल नहीं दिया है। भोपाल एम्स ने भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देने से मना किया है। सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की है। ट्विशा पक्ष के वकील शुभांग दीक्षित ने बताया कि अदालत पहले ही दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दे चुकी थी। इसके बाद 6 जुलाई को सीबीआई सैंपल लेने पहुंची थी। समर्थ सिंह ने वॉयस सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि गिरिबाला सिंह ने एक बार सैंपल दिया, लेकिन दोबारा सैंपल नहीं दिया। सुनवाई के दौरान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। वकील शुभांग दीक्षित के मुताबिक, भोपाल एम्स ने अदालत को बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और उससे जुड़े सभी दस्तावेज पहले ही (एजेंसी)। को सौंपे जा चुके हैं। इसलिए अलग से रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। वहीं, दिल्ली एम्स की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

पीओके में बड़ा बवाल

पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 6 लोगों की मौत

भारत ने कहा-

व्यवस्थित शोषण का नतीजा

इस्लामाबाद/नईदिल्ली (एजेंसी)। गुलाम कश्मीर (पीओके) में लगातार तनाव बढ़ रहा है। मंगलवार को रावलकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने आम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की। जिसके बाद शहर के नए बस टर्मिनल के पास झड़प फिर से शुरू हो गई। इन झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में छह आम नागरिक मारे गए। मारे गए लोगों में जाहिद मुगल, जफर मुगल, अर्सलान अकबर और वाजिद हयात शामिल थे। वाजिद हयात की मौत रावलकोट के मटियाल मीरा बस टर्मिनल पर हुई। इस ताजा हिंसा से इलाके में तनाव और बढ़ा दिया है, जहां इस्लामाबाद के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ रही है।

पीओके की आवाज व्हाइट हाउस तक पहुंची

इस हिंसा से ठीक एक दिन पहले, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर समुदाय के लोग वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए। उन्होंने इलाके में तेजी से बिगड़ते मानवीय संकट की ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की मांग की।

भारत से दखल देने की अपील

प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से चल रहे इंटरनेट शटडाउन का मुद्दा भी उठाया। उनका दावा था कि इसके कारण लगभग 40 लाख लोग बाहरी दुनिया से कट गए हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रभावित

निवासियों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए पुंछ और डोडा सेक्टर के जरिए नियंत्रण रेखा को खोला जाए।

भारत ने की पाकिस्तान की आलोचना

इस मामले पर मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये झड़पें व्यवस्थित शोषण का नतीजा हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित रखने और उसके अवैध व जबरन कब्जे वाले इलाकों में प्रशासनिक दमन का सीधा परिणाम हैं।

राममंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष बोले

चढ़ावे से 3 करोड़ चोरी हुए

अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर- दिल में बाबर, मुंह में राम

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि ने कहा- जहां तक मेरा अनुमान है करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई होगी। 14 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी होने की बात गलत है। गोविंददेव गिरि ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इस्तीफे की खबरों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा- मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है।

इधर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र का नाम हटा दिया गया है। इससे पहले दोनों की वीआईपी पास आईडी भी ब्लॉक कर दी गई थी। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास के नाम पर नई वीआईपी पास आईडी जारी की गई है।

अयोध्या, बाराबंकी, मथुरा समेत यूपी के कई जिलों में सोमवार देर रात सपा के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इनमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ लिखा है- दिल में बाबर, मुंह में राम। मंगलवार सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स फाड़ दिए।

आरोपी टिन्नू और सुभाष की रिमांड मांगेगी पुलिस- चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस दोनों की 7 दिन की रिमांड मांग सकती है। रिमांड मिलने पर दोनों से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले, पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।

11 साल में तीसरी बार मानसून पर ब्रेक

यूपी में अब तक 19 प्रतिशत, एमपी में 3 प्रतिशत कम बारिश

नई दिल्ली/लखनऊ/भोपाल (एजेंसी)। देश के बड़े हिस्से में जुलाई में मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बनी है। साल 2015 और 2021 के बाद 11 साल में यह तीसरा मौका है। मौसम विभाग के मुताबिक 6-7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार कम हैं। हालांकि, पूर्वोत्तर, बिहार और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश जारी रहेगी।

मध्य प्रदेश में पहली बार जुलाई में मानसूनी सीजन में कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 241.8 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश 250.1 मिमी से 3 प्रतिशत कम है।

वहीं, उत्तर प्रदेश में 1 जून से 13 जुलाई के बीच 161.6 मिमी बारिश हुई, जो कि औसतन 199.7 मिमी से 19 प्रतिशत कम है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कहीं भी बारिश नहीं हुई। श्रीगंगानगर में अधिकतम पारा 41.5 डिग्री रहा।

नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में बाढ़ जैसे हालात

पूर्वोत्तर में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बिहार, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल में लैंडस्लाइड और बाढ़ की खबरें सामने आ रही हैं। सोमवार को अरुणाचल के कुरुंग कुमे जिले में कुमे नदी में बाढ़ के बाद भारत-चीन सीमा के पास टापा बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात आईटीबीपी के 15 जवानों से संपर्क टूट गया। असम के टियोक में पुथी नदी ने एक तटबंध तोड़ दिया। कई गांव और कृषि भूमि पानी में डूब गए हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट गई।

नासिक में पर्यटकों पर हमला, 15 किमी तक पीछा किया

● चलती कार पर पत्थर-रॉड मारे, पीड़ित परिवार ने महिला से छेड़छाड़ का विरोध किया था

नासिक (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नासिक में घूमने गए एक पर्यटक परिवार पर मनचलों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने एक महिला से छेड़छाड़ की थी। परिवार ने इसका विरोध किया तो 8-10 युवकों ने परिवार को घेर लिया। महिला का परिवार किसी तरह कार से वहां से भागा। इसके बाद आरोपियों ने बाइकों से कार का करीब 15 किमी तक पीछा किया और लाठी-डंडों, रॉड और बेसबॉल स्टिक से उन पर जानलेवा हमला किया और चलती कार में तोड़फोड़ की। परिवार ने किसी तरह जान बचाई। वारदात सोमवार शाम की है। इस मामले में पुलिस ने लूट, हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले दर्ज कर 8 युवकों को अरेस्ट किया है।

धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दोनों दोषियों की उम्र कैद की सजा रहेगी बरकरार

धनबाद((एजेंसी)। झारखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद हत्याकांड में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों आरोपियों की ओर से दायर अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही धनबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी।

यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने पेश की दावेदारी

● विदेश मंत्री जयशंकर ने की कैंपेन की शुरुआत

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर 2028-29 के कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की दावेदारी का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि यूएनएससी में भारत की रणनीति (सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी) के सिद्धांतों पर होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लॉन्च किया 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म'

पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी

लॉन्चिंग से पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी। यह व्यवस्था देश में पंचायतों के पूर्णतः डिजिटल रिमोट वित्तीय ऑडिट की दिशा में अपनी तरह की अभिनव पहल है।

प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों में ऑडिट प्रक्रिया होगी तेज

केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के समयबद्ध ऑडिट की अनिवार्यता है। भारत के महालेखाकार के निर्देशन में पंचायती राज संचालनालय द्वारा एनआईसी के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन ऑडिट के लिए दृष्टि नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑडिटर अपने घर या ऑफिस से किसी भी पंचायत के सभी प्रकार के आय व्यय सम्बन्धी अभिलेख देख सकते हैं तथा उनकी जांच कर सकते हैं।

यह ऑडिट प्रक्रिया प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों के वित्तीय ऑडिट को तेज, सरल एवं पारदर्शी बनाएगी। इसके उपयोग से सीमित कर्मचारियों द्वारा भी समस्त पंचायतों का ऑडिट समय पर किया जा सकेगा। इस प्रणाली के क्रियान्वयन से समय और संसाधनों की बचत के साथ वित्तीय जवाबदेही और सुशासन को मजबूती मिलेगी।

पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे का भी हुआ शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विकसित दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक के दौरान हुई इस

इन नवाचारों से विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही के साथ सुशासन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पर आरंभ पेमेंट गेटवे पंचायत राज संचालनालय द्वारा एनआईसी, जल निगम एवं यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके माध्यम से पंचायतें नागरिकों के बिल जेनरेट कर सकेगी। गेटवे पर कोई भी नागरिक बिल का पेमेंट घर बेठे कर सकता है और ऑनलाइन ही रसीद भी प्राप्त कर सकता है। इससे लोगों के श्रम और समय दोनों की बचत होगी तथा पंचायत का अभिलेख भी स्वतः ही निर्मित होता चला जायेगा। सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यों का समयबद्ध निस्तारण होगा। इन नवाचारों से विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही अधिक होने के साथ ही सुशासन को बढ़ावा भी मिलेगा।

भोपाल की सड़कों पर आवारा मवेशियों का डेरा

बारिश में बढ़ गया हादसों का खतरा, इन इलाकों में निकलना हुआ मुश्किल

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आवारा मवेशियों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब शहर के मुख्य कमर्शियल और रिहायशी इलाके भी इससे अछूते नहीं रहे। बारिश शुरू होते ही मवेशी झुंड बनाकर सड़कों के बीचों-बीच बैठने लगे हैं, जिससे रोजाना ट्रैफिक जाम और गंभीर सड़क हादसे हो रहे हैं।

विशेष रूप से रात के समय या भारी बारिश के दौरान, अंधेरी और कम रोशनी वाली सड़कों पर अचानक मवेशियों के सामने आ जाने से दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक लगातार चोटिल हो रहे हैं।

नगर निगम की सुस्ती और नीतिगत कमियां- भोपाल में आवारा पशुओं की समस्या नई नहीं है, लेकिन नगर निगम की कैटल-कैचिंग मुहिम सिर्फ कागजी खानापूर्ति और रस्म अदायगी बनकर रह गई है। जब तक शहर के रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध डेयरियों को पूरी तरह बाहर शिफ्ट नहीं किया जाता, तब तक यह समस्या जस की तस रहेगी। केवल आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि उनके मालिकों के खिलाफ सीधे आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज न हो। ट्रैफिक पुलिस का यह सुझाव बेहद सटीक है कि दोबारा गलती करने पर मवेशी जब्ती और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान तुरंत लागू होना चाहिए ताकि लोगों की जान बच सके।

इन वीआईपी और पॉश कॉलोनियों में सबसे बुरा हाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह समस्या केवल रातीबड़, नीलबड़ या कटारा हिल्स जैसे बाहरी इलाकों तक सीमित नहीं है। शहर के सबसे पॉश माने जाने वाले गुलमोहर, शाहपुरा, शाहपुरा लेक, त्रिलंगा, कोलार रोड, एमपी नगर और अरेरा कॉलोनी जैसे व्यस्ततम रास्तों पर भी दर्जनों गाय और सांड डेरा जमाए रहते हैं। गुलमोहर निवासी अखिलेश कुमार ने बताया कि इस इलाके में अवैध रूप से चल रही डेयरियों के संचालक दूध निकालने के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, जो दिन-रात मुख्य मार्गों पर घूमते रहते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर

हाई कोर्ट ने नई प्रमोशन पॉलिसी पर रोक लगाने से किया इनकार

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट से एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी-2025 के तहत दी जा रही पदोन्नतियों पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रमोद मित्तल की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी और पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई थी।

2016 से अटका था मामला- गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को अवैध घोषित किए जाने के बाद से, साल 2016 से मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पूरी तरह ठप थे। इसके बाद सरकार ने 2025 में नई नीति लागू की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने केवल मामूली बदलाव करके पुरानी नीति को ही दोबारा पेश कर दिया है। हालांकि, हाई कोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल सरकारी विभागों में हो रहे प्रमोशन जारी रहेंगे, लेकिन ये सभी पदोन्नतियां इस मामले में आने वाले अंतिम अदालती फैसले के अधीन होंगी।

कुशल संगठनकर्ता थे पूर्व मुख्यमंत्री जोशी उनके किए कार्य हमारे लिए आदर्श : मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में स्व. जोशी के चित्र पर की पुष्पांजलि अर्पित

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कैलाश जोशी की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. कैलाश जोशी का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि श्री जोशी कुशल संगठनकर्ता और समाजसेवी थे, स्व. श्री जोशी उन्होंने 1962 में बागली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलता से निर्वाहन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. कैलाश जोशी का जीवन सादगी, शुचिता, जनसेवा और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा। प्रदेश के विकास और जनकल्याण के प्रति उनका अमूल्य योगदान सदैव प्रेरणादायी और स्मरणीय रहेगा। राज्य सरकार उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्षों की जयंती एवं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम की पहल सराहनीय है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री स्व. जोशी के पुत्र एवं पूर्व मंत्री श्री दीपक जोशी सहित परिजन उपस्थित थे।

● **विधानसभा सचिवालय में एक दशक बाद 182 अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति, विस अध्यक्ष श्री तोमर का किया गया सम्मान-** मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय में लगभग एक दशक के लंबे अंतराल के बाद विभिन्न संवर्गों के, प्रथम श्रेणी 15, द्वितीय श्रेणी 40, तृतीय श्रेणी 93 एवं चतुर्थ श्रेणी के 34 कुल 182 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हुआ। इस अवसर पर पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उनका पुष्पगुच्छ, शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कहा कि माननीय अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी के अथक प्रयासों, सकारात्मक पहल एवं मार्गदर्शन से वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण हो सकी, जिससे कर्मचारियों में नया उत्साह एवं कार्य के प्रति नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान 2026 को मिली बड़ी सफलता

3355 शिविरों में 1 लाख 47 हजार 633 शिकायतों का मौके पर निराकरण

भोपाल/ग्वालियर। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का उनके घर के नजदीक त्वरित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित संपर्क अभियान 2026 को उल्लेखनीय सफलता मिली है। 14 मई से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के अंतर्गत भोपाल एवं ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में अब तक 3355 विशेष शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 1 लाख 47 हजार 633 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया।

भोपाल रीजन के वृत्तों में लगे शिविर

भोपाल रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त भोपाल में 249 शिविरों में 16,010 शिकायतों का निराकरण किया गया। बैतूल वृत्त में 296 शिविरों में 15,741 शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ओ एंड एम) वृत्त में 159 शिविरों में 4,876 शिकायतों का निराकरण, हरदा वृत्त में 89 शिविरों में 13,671 शिकायतों का निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 250 शिविरों में 20,966 शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 171 शिविरों में 11,739 शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 239 शिविरों में 3,163 शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 229 शिविरों में 5,446 शिकायतों का निराकरण तथा विदिशा वृत्त में 119 शिविरों में 7,102 शिकायतों का निराकरण किया गया।

ग्वालियर रीजन के वृत्तों में लगे शिविर- ग्वालियर रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त ग्वालियर में 199 शिविरों में 4,023 शिकायतों का निराकरण किया गया। अशोकनगर वृत्त में 99 शिविरों में 9,014 शिकायतों का निराकरण, भिंड वृत्त में 190 शिविरों में 4,042 शिकायतों का निराकरण, दतिया वृत्त में 117 शिविरों में 5,741 शिकायतों का निराकरण, गुना वृत्त में 171 शिविरों में 6,082 शिकायतों का निराकरण, ग्वालियर (ओ एंड एम) वृत्त में 168 शिविरों में 3,144 शिकायतों का निराकरण, मुरैना वृत्त में 259 शिविरों में 7,850 शिकायतों का निराकरण, श्योपुर वृत्त में 126 शिविरों में 3,990 शिकायतों का निराकरण तथा शिवपुरी वृत्त में 225 शिविरों में 5,033 शिकायतों का निराकरण किया गया।

छतरपुर में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात

महिला को पीटते-पीटते थके आरोपी पानी पी-पीकर फिर बरसाईं लाठियां, मौत

छतरपुर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 55 साल की बुजुर्ग महिला हरकुंवर प्रजापति को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक खौफनाक वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर महिलाएं पीटते-पीटते थकने पर बीच में रुककर पानी पीती हैं और फिर असहाय पड़ी बुजुर्ग पर दोबारा लाठियां बरसाने लगती हैं।

यह पूरी वारदात 11 जुलाई को हुई, जब भारी बारिश के बाद हरकुंवर अपने घर के बाहर जमा पानी निकालने के लिए निकली थीं। तभी पुरानी रंजिश के चलते विरोधी परिवार के लोगों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। इलाज के दौरान पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया।

पुलिस पर लापरवाही के आरोप- मृतका के बेटे राजेंद्र प्रजापति ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेंद्र का कहना है कि जब उनकी मां को बेरहमी से पीटा जा रहा था, तब पुलिस की डायल-112 टीम मौके पर ही मौजूद थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने हमलावरों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की।

नेतृत्व पद से नहीं, व्यक्तित्व से प्रभावशाली बनता है : बीके नीता दीदी

जनसेवा में आध्यात्मिकता का समावेश ही सुशासन की पहचान : बीके आराधना

नगर निगम महापौर एवं पार्षदों का ब्रह्माकुमारीज़ में सम्मान, राजयोग से प्रभावी नेतृत्व का संदेश

भोपाल। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के सुख-शांति भवन, नीलबड़ में नगर निगम महापौर श्रीमती मालती राय एवं नगर निगम के समस्त पार्षदों के सम्मान में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ उन्हें आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित तनावमुक्त, प्रभावी एवं जनकल्याणकारी नेतृत्व का संदेश देना था।

कार्यक्रम में विशेष रूप से महापौर श्रीमती मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी, पूर्व अपर कलेक्टर श्री जी.पी. मोदी, ज्योतिषाचार्या पूनम जी, ब्रह्माकुमारीज़ भोपाल की संचालिका राजयोगिनी बीके नीता दीदी, राजयोगिनी बीके आराधना दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके राम कुमार भाई जी,बीके नारायण भाई, बीके पूनम बहन, बीके हेमा बहन, बीके आशीष भाई एवं बड़ी संख्या में नगर निगम के पार्षदगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बीके आशीष भाई द्वारा सभी अतिथियों के आत्मीय एवं प्रेरणादायी शब्दों से स्वागत के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि समाज की आशाओं और विश्वास के प्रतीक हैं तथा आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त नेतृत्व ही सशक्त एवं संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकता है। इसके पश्चात बीके पूनम बहन ने विभिन्न प्रेरणादायी गतिविधियों (इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़) के माध्यम से

उपस्थित जनप्रतिनिधियों को सकारात्मक सोच, टीम भावना, विश्वास, सहयोग एवं आत्मचिंतन का अनुभव कराया। इन रोचक गतिविधियों ने न केवल सभी को आनंदित किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जीवन और सेवा में सफलता के लिए मानसिक संतुलन, आपसी सामंजस्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है।

इसके पश्चात वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके राम भाई जी ने तनावमुक्त जीवन से प्रभावी सेवा विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज अधिकांश तनाव का मूल कारण अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाना है। हम स्वयं को शरीर, पद और परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं, जबकि हमारी वास्तविक पहचान शांति, प्रेम और आनंद स्वरूप आत्मा की है। आत्मा के तीन प्रमुख उपकरण मन, बुद्धि और संस्कार हैं। मन में सकारात्मक विचार, बुद्धि में सही निर्णय और श्रेष्ठ संस्कार ही तनावमुक्त एवं सफल जीवन का आधार हैं।

उन्होंने कहा कि तनाव का प्रभाव केवल मन पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, संबंधों और निर्णय क्षमता पर भी पड़ता है।

फर्नीचर शोरूम-गोदाम में भीषण आग

सोफा, बेड-अलमारी से भरे थे, 5 घंटे में काबू पाया

भोपाल (नप्र)। भोपाल के हमीदिया रोड स्थित एक फर्नीचर शोरूम और गोदाम में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। इससे सोफा, बेड-अलमारी समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया।आग सुबह साढ़े 5 बजे लगी, जो 10:20 बजे काबू में आ पाई। इस तरह करीब 5 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका।

फतेहगढ़, बोगदा पुल, कबाड़खाना, बैरागढ़ और गांधीनगर से दमकलें मौके पर पहुंचीं। फायर फाइटर नौशाद अली ने बताया कि दमकल और टैंकरों के जरिए आग काबू में की गई।

संपादकीय

अब जम्मू-कश्मीर में टकराव!

लगता है अब भाजपा ने जम्मू कश्मीर में भी नया मोर्चा खोल दिया है। कुछ लोग इसे वहां का 'ऑपरेशन लोटस' भी कह रहे हैं। आरोप है कि भाजपा अब वहां भी विपक्षी पार्टियों में तोड़फोड़ करने जा रही है। इन अटकलों तक बल मिला, जब राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह हजरतबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू क्षेत्र के एक एनसी विधायक ने उन्हें बताया कि बीजेपी की ओर से उन्हें पार्टी छोड़ने के बदले 20 से 30 करोड़ रुपये नकद, मंत्री पद और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने का आश्वासन दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने यह आरोप भी लगाया था कि इस पूरी कोशिश में बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल थे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। इस आरोप से भड़की बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बीजेपी ने क़ानूनी नोटिस भेजकर सात दिनों में अपनी बात वापस लेने और माफ़ी मांगने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर सिविल व आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला द्वारा उस पर लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताते हुए सात दिनों के भीतर लिखित रूप में बयान वापस लेने और बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा समेत सिविल और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के इस लेटर पर तंज कसते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें 'लव लेटर' भेजा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस झूठे बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी ऐसे नोटिस भेजेगी। इससे साबित होता है कि मैं ऐसी राजनीतिक ताक़त हूँ जिसे बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने एक राजनीतिक बयान दिया था और उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उसका राजनीतिक जवाब देगी। लेकिन 'यह बीजेपी की राजनीति करने का तरीका है। राजनीतिक लड़ाई को अदालत के पीछे छिपकर लड़ना उनकी आदत है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी की ओर से अधिवक्ता परिमोक्ष सेठ के माध्यम से यह क़ानूनी नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत पाल शर्मा के निर्देश पर जारी किया गया। तीन पन्नों के इस नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आरोप पूरी तरह झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बिना किसी तथ्यात्मक आधार के हैं। पार्टी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला के बयानों से बीजेपी और उसके पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा को गंभीर नुक़सान पहुँचा है। नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल हुए चुनाव के बाद राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस और भाजपा के बीच अघोषित सौहार्द्र क्या खत्म हो गया है? राज्य में नेशनल कांफ्रेंस को तोड़कर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है और क्या नेशनल कांफ्रेस तो तोड़कर राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने की कितनी संभावना है? जाहिर है कि बीजेपी के सत्ता में आने की उम्मीद नहीं के बराबर है। दरअसल उमर अब्दुल्ला राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिए जाने से नाराज हैं। लिहाजा उन्होंने दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा से टकराव शुरू कर दिया है। लेकिन इससे लाभ क्या होगा, यह समझना मुश्किल है।

दलित राजनीति की जंग में आमने-सामने मायावती व चंद्रशेखर

नजरिया

अजय कुमार
लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित नेतृत्व को लेकर जो बहस लंबे समय से भीतर ही भीतर चल रही थी, वह अब खुलकर सामने आ गई है। मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड के बाद आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद के आंदोलन और उस पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की तीखी प्रतिक्रिया ने इस बहस को नई दिशा दे दी है। मायावती ने बिना नाम लिए ऐसे आंदोलनों को 'मगरमच्छ के आंसू' और 'संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ' से जोड़ते हुए दलित समाज को सड़क की बजाय संविधान और न्यायपालिका के रास्ते पर चलने की सलाह दी। इसके जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि जब समाज पर अत्याचार हो रहा हो, तो केवल अदालतों का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। यह विवाद केवल दो नेताओं की बयानबाजी नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में नेतृत्व और रणनीति की नई लड़ाई का संकेत है।

मायावती का राजनीतिक दर्शन हमेशा सत्ता के जरिए सामाजिक परिवर्तन का रहा है। कांशीराम ने जिस 'मास्टर चाबी' का सिद्धांत दिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मायावती लगातार कहती रही हैं कि सत्ता हासिल किए बिना बहुजन समाज का स्थायी उत्थान संभव नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि बसपा सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी राजनीति में विश्वास नहीं करती। उनका कहना है कि गरीब, मजदूर और बेरोजगार नौजवान यदि आंदोलनों के दौरान मुकदमों में फंसेंगे, तो उनका भविष्य बर्बाद होगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज को ही उठाना पड़ेगा। यह संदेश केवल वर्तमान आंदोलन तक सीमित नहीं था, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले बसपा की पूरी राजनीतिक रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है।

दिलचस्प यह है कि मायावती के इस बयान का समर्थन बीजेपी के वरिष्ठ नेता संगीत सोम ने भी किया। उन्होंने कहा कि समाज को दलालों और उकसाने वालों से बचना चाहिए। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने तीखा हमला बोला। इस समर्थन ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी, क्योंकि लंबे समय से विपक्ष मायावती पर बीजेपी के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि, बसपा लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है और खुद को सभी दलों से समान दूरी रखने वाली पार्टी बताती है।

अगर पिछले डेढ़ दशक का राजनीतिक इतिहास देखें, तो तस्वीर और भी रोचक दिखाई देती है। वर्ष 2007 में मायावती ने 'सर्वजन' सामाजिक इंजीनियरिंग के सहारे उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यह बसपा का स्वर्णकाल माना जाता है। लेकिन 2012 में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा पहली बार शून्य सीट पर पहुंची। 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल 19 सीटों तक सिमट गई। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जरूर जीतीं, लेकिन गठबंधन ज्यादा समय नहीं चला। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी फिर शून्य पर पहुंच गई। चुनावी आंकड़ों के अनुसार, 2007 में करीब 30 प्रतिशत वोट पाने वाली बसपा का वोट प्रतिशत अब लगभग 10 से 13 प्रतिशत के बीच सिमट चुका है। यह गिरावट दलित राजनीति में बदलते समीकरणों की सबसे बड़ी कहानी कहती है।

यहीं से चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का विस्तार शुरू होता है। 2017 के सहारनपुर शब्बीरपुर हिंसा के बाद भीम आर्मी के जरिए उन्होंने दलित युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल जाना, फिर बाहर आकर सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन, दलित अत्याचार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहना उनकी राजनीति का आधार बना। 2020 में आजाद समाज पार्टी का गठन और 2024 में नगीना लोकसभा सीट से अकेले चुनाव जीतना इस बात का संकेत था कि दलित राजनीति में अब नया नेतृत्व भी जगह बना रहा है। खास बात यह रही कि उन्होंने यह जीत किसी बड़े गठबंधन के बिना हासिल की। इसके बाद से वह उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, पंजाब और दूसरे राज्यों में भी संगठन विस्तार की कोशिश कर रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित वोट अब पहले जैसा एकमुश्त नहीं रहा। जाटव समुदाय का बड़ा हिस्सा आज भी बसपा के साथ जुड़ा माना जाता है, लेकिन गैर-जाटव दलितों में पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव आया है। एक हिस्सा बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक प्रतिनिधित्व के कारण उसके साथ गया, जबकि दूसरा हिस्सा स्थानीय आंदोलनों और चंद्रशेखर जैसे नए नेताओं की ओर आकर्षित हुआ। यही कारण है कि दलित राजनीति अब केवल बसपा बनाम बाकी दल नहीं रह गई, बल्कि उसके भीतर भी प्रतिनिधित्व की नई लड़ाई शुरू हो गई है।

मायावती इस बदलाव को अच्छी तरह समझती हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने लगातार संगठन को मजबूत करने, अकेले चुनाव लड़ने और कार्यकर्ताओं को आंदोलन की बजाय बूथ स्तर पर जुटने का संदेश दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बसपा किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और 2027 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। पार्टी लगातार 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' और कानून-व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बताकर पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पूरी तरह आंदोलन आधारित दिखाई देती है। उनका तर्क है कि केवल चुनाव जीतने से सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि सड़क पर संघर्ष भी जरूरी है। यही वैचारिक अंतर आज दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक फर्क बन गया है। एक तरफ मायावती संविधान, अदालत और सत्ता की राजनीति पर भरोसा जताती हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर संविधान के साथ-साथ जन आंदोलन को भी बराबर जरूरी मानते हैं। ललिता गौतम हत्याकांड के बाद दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने इस अंतर को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट कर दिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल 2027 को लेकर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार होनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता बचाने की तैयारी में है, समाजवादी पार्टी 2024 की लोकसभा सफलता को विधानसभा में दोहराना चाहती है और कांग्रेस भी संगठन विस्तार में जुटी है। ऐसे में दलित वोट किस दिशा में जाएगा, यह चुनाव का निर्णायक कारक बन सकता है। यदि बसपा अपना पारंपरिक वोट बैंक बचाने में सफल रहती है, तो मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। लेकिन यदि चंद्रशेखर गैर-जाटव दलित युवाओं और आंदोलनकारी राजनीति को और मजबूत आधार दे देते हैं, तो बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि अपने ही सामाजिक आधार के भीतर से खड़ी होती दिखाई दे सकती है। यानी, मौजूदा विवाद केवल एक बयान या एक आंदोलन का नहीं है। यह उस बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है, जिसमें उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति पहली बार दो अलग-अलग रास्तों के बीच खड़ी दिखाई दे रही है एक रास्ता मायावती का, जो सत्ता को परिवर्तन का माध्यम मानता है, और दूसरा चंद्रशेखर आजाद का, जो सड़क के संघर्ष को राजनीतिक ताकत में बदलना चाहता है। 2027 का चुनाव शायद यह तय करेगा कि बहुजन राजनीति की अगली पीढ़ी किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी।

मध्य प्रदेश में तकनीक आधारित उद्योग विकास

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव

डॉ. मयंक चतुर्वेदी
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भारत में पिछले एक दशक हुए डिजिटल परिवर्तनों ने राष्ट्रीय विकास के आगे उसे आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास की धुरी बनाया है। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने देश को नई तकनीकी दिशा दी है। इसी राष्ट्रीय दृष्टि को राज्य स्तर पर गति देने का प्रयास इन दिनों मध्यप्रदेश में होता हुआ देखा जा सकता है, जिसमें कि 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0' उसी परिवर्तन का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे सामने है।

यह सम्मेलन निश्चित ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उस नई आर्थिक सोच का परिचायक है, जिसमें मध्यप्रदेश स्वयं को कृषि प्रधान राज्य की पारंपरिक छवि से आगे बढ़ाकर भारत के उभरते हुए हाई-टेक औद्योगिक और डिजिटल केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है।

वस्तुतः जैसा कि मुख्यमंत्री कई अवसरों पर कहते भी रहे हैं कि विश्व बैंक और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अध्ययनों में लगातार यह बात सामने आई है कि भविष्य की आर्थिक प्रतिस्पर्धा डिजिटल प्रौद्योगिकी, ज्ञान आधारित उद्योगों और नवाचार क्षमता पर आधारित होगी। उत्पादन से अधिक मूल्य अब डिजाइन, डेटा, अनुसंधान और डिजिटल सेवाओं से उत्पन्न हो रहा है। मध्यप्रदेश ने इसी परिवर्तन को समय रहते समझा है। लंबे समय तक कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पारंपरिक विनिर्माण पर आधारित अर्थव्यवस्था अब तकनीकी निवेश की ओर बढ़ रही है।

आज एक बार फिर राज्य की राजधानी भोपाल में आयोजित कॉन्क्लेव में 178.70 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इन इकाइयों से 1,229 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इसी अवसर पर गूगल प्ले (इंडिया लीड), मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कई दिग्गज कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान भी हुआ। साथ ही स्पेन की Submer India Private Limited सहित विभिन्न कंपनियों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए गए, जो यह दर्शाता है कि मध्यप्रदेश वैश्विक तकनीकी कंपनियों के निवेश मानचित्र पर अपनी जगह बना रहा है।

इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मोहन सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये के संभावित निवेश के साथ 35 हजार रोजगार का लक्ष्य रखा है। यदि यह निवेश प्रस्ताव समयबद्ध ढंग से परियोजनाओं में बदलते हैं, तो प्रदेश की औद्योगिक संरचना में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा।ऐसे निवेशों का प्रभाव दूरगामी होता है। इनके साथ सहायक उद्योग, लॉजिस्टिक्स, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से विकसित होते हैं। यही कारण है कि तकनीकी निवेश को आधुनिक अर्थव्यवस्था का 'मल्टीप्लायर सेक्टर' माना जाता है।

यहां ध्यान देने योग्य यह भी है कि इससे पूर्व प्रदेश में सम्पन्न हुए एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के पहले दो आयोजनों ने निवेश की रफ्तार को नई गति दी है। कॉन्क्लेव 1.0 में राज्य को 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिससे करीब 75 हजार रोजगार के अवसर बने। दूसरे एडिशन (कॉन्क्लेव 2.0) में 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया, जिससे 48 हजार युवाओं को रोजगार मिला। अब यह अपने में सफलता के साथ इस दिशा में तीसरा कॉन्क्लेव सम्पन्न हुआ है।

यहां यह भी बताया गया है कि प्रदेश में 1 गीगावाट क्षमता वाले एआई डेटा सेंटर की परियोजना साकार होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड सेवाओं, डिजिटल बैंकिंग, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स का पूरा ढांचा डेटा सेंटरों पर निर्भर है। भारत में डिजिटल सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए डेटा सेंटर उद्योग आने वाले वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में शामिल माना जा रहा है। यदि मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में समय रहते मजबूत आधार तैयार करता है, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

इसी तरह से आज मोबाइल फोन से लेकर रक्षा उपकरण, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिक वाहन और अंतरिक्ष तकनीक तक हर क्षेत्र की आधारशिला सेमीकंडक्टर हैं। इसी प्रकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वे संस्थान हैं, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनुसंधान, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर विकास और वैश्विक परिचालन संचालित करती हैं।

यदि मध्यप्रदेश इन दोनों क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है, तो प्रदेश में रोजगार के साथ उच्च कौशल वाले पेशेवरों का नया वर्ग भी तैयार होगा। इससे राज्य की आय, नवाचार क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि होगी। वहीं, इंदौर सुपर कॉरिडोर, भोपाल आईटी पार्क के विस्तार तथा कोलार रोड पर प्रस्तावित नए आईटी पार्क इस बात का संकेत हैं कि सरकार निवेश को लेकर गंभीर है, इसलिए उसके लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा भी तैयार कर रही है।

ऐसे में कहना यह भी है कि मध्यप्रदेश की यह पहलें उस समय सामने आई हैं, जब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया, इंडिया एआई मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया, पीएलआई (Production Linked Incentive) योजनाओं तथा स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से तकनीकी विनिर्माण और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। यदि राज्य सरकार इन राष्ट्रीय पहलों के साथ अपने औद्योगिक विकास मॉडल का प्रभावी समन्वय करने में सफल रहती है, तो यह तय है कि राज?य को अतिरिक्त निवेश, तकनीकी सहयोग और वैश्विक कंपनियों की भागीदारी का व्यापक लाभ मिलेगा।

कुल मिलाकर कहें तो एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 यह संकेत देता है कि मध्यप्रदेश अब भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर अपनी विकास रणनीति तैयार कर रहा है। कृषि, विनिर्माण और तकनीक इन तीनों क्षेत्रों का संतुलित विकास प्रदेश को नई आर्थिक शक्ति प्रदान कर सकता है।यदि राज्य इन सभी मोर्चों पर समान गति से आगे बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ युरोप के प्रमुख हाई-टेक निवेश और नवाचार केंद्रों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर पाने में सफल होगा। हम उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस दिशा में जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके ये सभी प्रयास पूर्णता को प्राप्त करें।

विश्व राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

पीओके की आजादी की आवाज लंदन पहुंची

पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर अशांत है और वहां जनाक्रोश दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। पिछला पूरा पखवाड़ा पीओजेके, गिलगित और बाल्टिस्तान में हड़ताल, रास्ता रोको और प्रदर्शनों में बीता है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की खास बात यह रही कि बाजारों में दुकानों के शटर गिरे रहे। कल तक जो आंदोलन मंहगाई, सब्सिडी और सुविधाओं को लेकर हुआ करता था, अब पाकिस्तान के कब्जे, प्रशासनिक नियंत्रण और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवाज में तब्दील हो गया है। आंदोलन के दमन के लिये पाकिस्तान की हुकूमत ने गिरफ्तारी, छापों और गोलियों की बौछार का सहारा लिया है। बिगड़ते हालात पर काबू के लिये उसने इलाके में करीब चौदह हजार पुलिसकर्मी तैनात किये हैं और आंदोलनकारी नेताओं की सुरागकशी के लिये एक करोड़ रूपयों के ईनाम का ऐलान किया है। इस्लामाबाद के लिये डर और फिक्र का सबब यह है कि मीरपुर, रावलकोट और मुजफ्फराबाद की सभाओं में अब वी वान्ट फ्रीडम और गो बैक पाकिस्तान के नारे लगने लगे हैं।

इसमें शक नहीं कि सिंतबर, सन 2023 में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के गठन के बाद समूचे इलाके में न सिर्फ आंदोलन में विस्तार और तेजी आई है, वरन अब उसकी नली पाकिस्तान के हुक्मरान की ओर मुड़ गई है। अब तक आंदोलन की कमान शौकत नवाज मीर, सरदार उमर नजीर, ख्वाजा मेहरान अर्शद, हफीज हमदानी और इम्तियाज असलम जैसे नेताओं के हाथों में रही है, लेकिन इधर सरदार अमन खान सर्वप्रमुख और मुखर नेता के तौर पर उभरे हैं। अमन खान तुर्श जुबां नेता हैं। हाल में रावलकोट की सभा में उन्होंने ज़ालिम निजाम को शिकस्त देने की अवाम से अपील की। अमन मानते हैं कि इलाके में पाक-फौज की मौजूदगी जरूरी नहीं है। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता खोलने के साथ-साथ वह यह भी कहते हैं कि भारत के साथ रिश्ता कैसा हो, यह इस्लामाबाद नहीं, वरन हम तय करेंगे।

स्पष्ट है कि पाक अधिकृत क्षेत्र में अवाम की सोच में वक्त के साथ परिवर्तन आ रहा है। जनता की मांगें अब बिजली कटौती, मंहगाई कम करने या सस्ता गेंहू मुहैया करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अब अपनी तकदीर की इबारतें खुद लिखने को बेताब हैं। वे मानते हैं कि पाकिस्तान ने इलाके को बेतरह लूटा है। उसे काश्मीरियों से नहीं, वरन इलाके की जमीनों-जायदाद से सरोकार है। सभाओं और जुलूसों में दिलचस्प तौर पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे तो लगते ही हैं, 'दहशतगर्दी के पीछे वर्दी' जैसी तीखी सेना विरोधी बातें और तोहमतें भी सुनी जाती हैं। सामूहिक सोच में आये इस काबिले गौर परिवर्तन के पीछे संचार साधनों का बड़ा हाथ है। इंटरनेट की आमद ने इलाके के लोगों तक जम्मू-काश्मीर के मेनलैण्ड की तस्वीर पहुंचाने का काम किया है। जम्मू काश्मीर में रेल सेवा, टनलिंग, हवाई अड्डों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य सुविधाओं के आगमन ने अधिकृत क्षेत्र के लोगों को अपनी दशा और दिशा के बारे में नये सिरे से सोचने को बाध्य किया है।

यह व्यापक प्रतिरोध का ही नतीजा है कि हालात पर काबू पाने में प्रशासन के हाथ-पाँव फूल रहे हैं। पिछले दिनों बिंबर से मुजफ्फराबाद तक के कूच से प्रशासन की पेशानी पर पसीना चुह चुहा आया। असंतोष चौतरफा और इतना घना था कि दमन और हिंसा के नजारे देखने को मिले। कम-अज-कम दो दर्जन नागरिक, ठौर मारे गये और लगभग 500 आहत हुये। बदले में भड़की हिंसा में चार पुलिसकर्मी मरे और अनेक घायल। सूचनाओं के मुताबिक हालात दिनोंदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में भी असंतोष ऊफान पर है। अधिकृत क्षेत्र में स्वायत्तता और अधिकारों की मांग का असर सीमांत क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। लेकिन आंदोलनकारियों से वार्ता के मूड में इस्लामाबाद नजर नहीं आता। उसने दमन का हथियार चुना है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को आतंकवादी संगठन घोषित कर अपने इरादों का संकेत दे दिया है। इधर पीओके में आवाम की आजादी की आवाज सात समुंदर पार विलायत तक पहुंच गयी है। पार्लमेंट स्वे यर से पाक-उच्चायोग तक निकले इस कूच को संबोधित करते हुये महमूद कश्मीरी ने कहा कि हम पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टकेंगे। प्रदर्शनकारियों ने आजादी के समर्थन में नारे लगाए और जाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख शौकत नवाज मीर और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की। देखना होगा कि अवाम की सोच में बदलाव बगावत की शक्ल अख्तियार करेगा या नहीं?

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सुरेश सौरभ
लेखक व्यंग्यकार हैं।

साहब लोगों की चाय का मतलब समझना

उस दिन मैं एक सरकारी दफ्तर में खड़ा था। वहां के चपरासी से पूछा, 'साहब कहां हैं ? हाउस टैक्स जमा करना है। कुछ समस्या है, उनसे मिलकर ही समाधान होगा।' वह बोला- 'साहब चाय पीने गए हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।' नजूल की जमीन पर बनी, उस सरकारी बिल्डिंग में पड़ी फरियादियों के इंतजार करने वाली बेंच पर पसर कर मैं बैठ गया।

आधा घंटा बीता, फिर घंटा बीतने लगा, तब मैंने व्यग्रता से उस चपरासी से पूछा- 'साहब कब तक आएंगे भाई।' उसने कुटिल मुस्कान से कहा- 'आते होंगे भाई थोड़ा इंतजार करो। साहब के पास एक ही काम थोड़ी हैं, अनेक कामों का उनके सिर पर बोझ है। 'मैंने ऊपर-नीचे ऐसे सिर हिलाया जैसे देश रक्षा के लिए जा रहे ,सैनिकों के लिए लोग भारी मन से सिर हिलाकर उन्हें जाने की मौन स्वीकृति देते हैं।

मैं साहब के ऑफिस में बार-बार झांक-झांक देखता, ऐसा न हो साहब अंदर वाले दरवाजे से आ जाएं और मैं बाहर बैठे-ठाले बस मोबाइल ही टीपता रहूं। खैर ऐसा नहीं हुआ साहब अंदर वाले दरवाजे से, अंदर नहीं आए। पूरे दो घंटे बाद कार्यालय की गैलरी में नमूदार हुए ,तेज़ी से अपने अर्दली के साथ अपने ऑफिस की ओर हंसते खिलखिलाते हुए पान मसाला चबर-चबर चबाते हुए, ऑफिस में प्रवेश कर रहे थे,सब्र हुआ हुजूर आए तो सही,तभी मेरे नथुनों में एकदम से कोई दुर्गंध आयी, लगा यह साहब के साथ आयी है, जो ऑफिस में उनके समां गयी। 'नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बड़े लोग हैं, इज्ज़तदार लोग हैं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता यह दुर्गंध कहीं और-तौर से आ रही होगी। खैर साहब से इजाजत ले जैसे ही उनके ऑफ़िस में मैं दाखिल हुआ,उफ़ लग रहा, इसी ऑफिस से आ रही है, साहब के करीब जैसे ही आया, अहसास हुआ, ठेका देसी शराब की दुकान के बिलकुल करीब आ गया हूं-साहब को जल्दी-जल्दी ये वो ये वो करके अपनी समस्याएं बताईं। मुझे सरकारी भाषा में ककहरा समझा कर साहब ने कहा , 'पूरा टैक्स तुम्हें ही जमा करना होगा ,मुआफी किसी तरह की नहीं होगी ,हां थोड़ा-थोड़ा करके किश्तों में जमा कर सकते हो।' मुझे उबकाई आने लगी जल्दी-जल्दी उनके ऑफिस से बाहर आया, तभी गैलरी में एक चाय वाला नज़र आया, जो साहब के ऑफिस में घुसता जा रहा था। दो घंटे बाद साहब, बाहर की चाय पीकर आए, अब यह अंदर की चाय पता नहीं कितने घंटे तक पिएं, मैं बुदबुदाता-भुनभुनाता हुआ अपना टैक्स किश्तों में जमा करने जा रहा था। अब चपरासी मुझे हैरत देख मुस्कुराते हुए बोला, 'हो गया काम।' मैंने कहा, 'हां सही टैम पर हो गया। वर्ना साहब की दूसरी चाय आ गयी थी, यह चाय तो भोर ही कर देती।'

मैं साहब के ऑफिस में बार-बार झांक-झांक देखता, ऐसा न हो साहब अंदर वाले दरवाजे से आ जाएं और मैं बाहर बैठे-ठाले बस मोबाइल ही टीपता रहूं। खैर ऐसा नहीं हुआ साहब अंदर वाले दरवाजे से, अंदर नहीं आए। पूरे दो घंटे बाद कार्यालय की गैलरी में नमूदार हुए ,तेज़ी से अपने अर्दली के साथ अपने ऑफिस की ओर हंसते खिलखिलाते हुए पान मसाला चबर-चबर चबाते हुए, ऑफिस में प्रवेश कर रहे थे,सब्र हुआ हुजूर आए तो सही,तभी मेरे नथुनों में एकदम से कोई दुर्गंध आयी, लगा यह साहब के साथ आयी है, जो ऑफिस में उनके समां गयी। 'नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बड़े लोग हैं, इज्ज़तदार लोग हैं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता यह दुर्गंध कहीं और-तौर से आ रही होगी। खैर साहब से इजाजत ले जैसे ही उनके ऑफ़िस में मैं दाखिल हुआ,उफ़ लग रहा, इसी ऑफिस से आ रही है, साहब के करीब जैसे ही आया, अहसास हुआ, ठेका देसी शराब की दुकान के बिलकुल करीब आ गया हूं-साहब को जल्दी-जल्दी ये वो ये वो करके अपनी समस्याएं बताईं। मुझे सरकारी भाषा में ककहरा समझा कर साहब ने कहा , 'पूरा टैक्स तुम्हें ही जमा करना होगा ,मुआफी किसी तरह की नहीं होगी ,हां थोड़ा-थोड़ा करके किश्तों में जमा कर सकते हो।

चपरासी हंसते हुए बोला- 'लग रहा साहब लोगों की चाय का मतलब समझ गये हो?' 'अच्छी तरह समझ गया, साहब की, बाहर की चाय का मतलब और अंदर की चाय का मतलब', यह कहते हुए मैं हाउस टैक्स जमा करने के लिए लाइन जा लगा और अपने नंबर आने का इंतजार करने लगा।

खौफनाक अपराध

डॉ. सुधीर कुमार

(कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर)

वैवाहिक पवित्रता और रिश्तों के अंतहीन अपराध

सप्तपदी के सात वचन दो आत्माओं के मिलन का आधार होते हैं। ये केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन भर साथ निभाने का एक संकल्प हैं। लेकिन, जब वही पवित्र अग्नि साक्षी बनकर किसी जीवन की अंतिम शैया बन जाए, तो यह केवल हत्या नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का विनाश है। इंदौर, पुणे और मेरठ से हुई हाल की घटनाएं मात्र अपराध की खबरें नहीं, बल्कि उस गहरे सामाजिक दंश का प्रमाण है, जहाँ सहनशीलता की जगह क्रूरता और संवाद की जगह साजिश ने ले ली। जिस घर को सुरक्षित आश्रय माना जाता था, वह आज प्यार, धोखे और कत्ल के क्रूर रणक्षेत्र में बदल चुका है, जो उस सामाजिक ढांचे के दरकने का संकेत है जिसे हमने सदियों से संस्कारों से बांधा था।

पतियों की पत्नियों द्वारा हत्या और पत्नियों की पतियों द्वारा हत्या की ताजा घटनाओं के मूल में रिश्तों में बढ़ता असंतोष, अवैध संबंध और 'त्वरित समाधान' की विकृत मानसिकता जिम्मेदार है। आधुनिकता की दौड़ और भागदौड़ भरी जिंदगी ने मनुष्य को इतना अधीर बना दिया है कि वह अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने के बजाय, उन्हें जड़ से मिटाने की घातक सोच पालने लगा है। आज के युग में 'सहनशीलता' एक लुप्तप्राय गुण हो गया है।

छोटी-छोटी असहमतियां अब लंबी बहस के बजाय अहंकार के टकराव में बदल जाती हैं। वैवाहिक जीवन में आने वाली सामान्य जटिलताओं या तलाक की लंबी और पेचीदा कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए लोग अपराध का रास्ता चुन रहे हैं। यह भ्रम कि वे कानून की नजरों से बच जाएंगे, उन्हें पतन की ओर ले जा रहा है। तकनीक और सोशल मीडिया ने रिश्तों की गोपनीयता को कम कर दिया है, जिससे असुरक्षा की भावना पनपती है। जब यह असुरक्षा ईर्ष्या और संदेह का रूप लेती है, तो तर्क खत्म हो जाता है और अपराधी की आपराधिक सोच हावी हो जाती है।

हालांकि, आधुनिक फॉरेंसिक साइंस, डीएनए प्रोफाइलिंग और पुलिस की उन्नत जांच पद्धति ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न बरते, डिजिटल युग में उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स उसे कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त हैं। आज की जांच में केवल शारीरिक साक्ष्य ही नहीं, बल्कि साइबर फॉरेंसिक की भूमिका अहम है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, गूगल सर्च हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट्स का विश्लेषण अपराध की कड़ियों को ऐसे जोड़ता है कि अपराधी का बचाव करना असंभव हो जाता है। कानून के लंबे हाथ अपराधियों को उनके मंसूबों में सफल नहीं होने देते। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, पति या पत्नी की हत्या की साजिश रचना एक 'प्री-मेडिकेटेड मर्डर' की श्रेणी में आता है। धारा 103 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड का स्पष्ट प्रावधान है, जबकि धारा 61 (आपराधिक साजिश) इन मामलों को और अधिक गंभीर बना देती है। न्यायालय में दोष सिद्धि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य निर्णायक भूमिका निभाते हैं। केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1962) जैसे ऐतिहासिक मामले और हालिया न्यायिक दृष्टांतों ने यह स्थापित किया है कि सुनियोजित तरीके से की गई हत्या, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में की गई हो, न्यायपालिका की कठोरता से बच नहीं सकती। आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल साक्ष्यों को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ जोड़कर दोषसिद्धि प्राप्त करना कानूनी रूप से एक पुख्ता आधार है। ऐसे मामले 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में आते हैं, जहां अदालतें कठोर दंड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखातीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'स्पूजल होमिसाइड' (दंपति हत्या) के मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके लिए कठोर 'फर्स्ट डिग्री मर्डर' का प्रावधान है, जिसके तहत आजीवन कारावास या कुछ राज्यों में मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम में 'डोमेस्टिक होमिसाइड रिव्यूज' की एक अनूठी व्यवस्था है, जो किसी भी हत्या के बाद एक अनिवार्य जांच के माध्यम से सिस्टम की खामियों को उजागर करती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे समाजों में पारिवारिक हत्याओं को न केवल कानून की नजर में जघन्य अपराध माना जाता है, बल्कि वहां अपराधियों को गहरे सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। यह सामाजिक दंड, कानूनी सजा से कहीं अधिक प्रभावी और मारक साबित होता है। इन जघन्य घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि केवल कानून का भय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यापक सामाजिक सुधार भी अनिवार्य हैं। समाधान की दिशा में सबसे पहले विवाह को केवल एक सामाजिक मिलन के बजाय मानसिक साझेदारी के रूप में देखने की जरूरत है, जिसके लिए विवाह-पूर्व परामर्श (प्री-मैरिटल काउंसलिंग) को बढ़ावा देना होगा ताकि मनोवैज्ञानिक अनुकूलता और जीवन की अपेक्षाओं पर स्पष्ट संवाद हो सके। साथ ही, समाज में इस कानूनी साक्षरता का प्रसार आवश्यक है कि विवाह का टूटना एक सम्मानजनक और कानूनी विकल्प हो सकता है, जबकि हत्या जैसा कृत्य केवल अंधकारमय जेल की ओर ले जाता है। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए ऐसे मामलों में फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से छह महीने के भीतर दंड सुनिश्चित करना होगा ताकि अपराधियों में कानून का डर बना रहे।

डिजिटल युग में सोशल मीडिया से उपजे अवैध संबंधों और उनसे जुड़ी विकृतियों पर नियंत्रण पाने के लिए हमें पारिवारिक संवाद की संस्कृति को पुनः जीवित करना होगा।

आज की शिक्षा प्रणाली में 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। स्कूलों और महाविद्यालयों के स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए जो युवाओं को विपरीत परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने, हार स्वीकार करने और असफल रिश्तों से गरिमापूर्ण तरीके से बाहर निकलने का कौशल सिखा सकें। जब तक हम नई पीढ़ी को 'अहंकार के प्रबंधन' की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक रिश्तों में हिंसक प्रवृत्तियां कम करना कठिन होगा। सनातन धर्म में विवाह 'करार' नहीं, 'संस्कार' है, जहाँ अग्नि को साक्षी मानकर दिए गए वचनों का उल्लंघन धर्म का त्याग है। शास्त्रों में 'दंपति' को एक इकाई माना गया है, जिसका पतन पूरी व्यवस्था को दूषित करता है। महात्मा गांधी ने कहा था, 'मनुष्य की हिंसा का अंत अंततः उसके स्वयं के विनाश से ही होता है।' ऐसे जघन्य कृत्य 'अधर्मी' हैं, जिनका प्रायश्चित केवल कठोर दंड है। कानून अपराधियों को दंडित करेगा, लेकिन समाज को अपनी चेतना जगाकर अपराध की जड़ों में छिपे उस अकेलेपन और असुरक्षा को पहचानना होगा, जो व्यक्ति को पतन की ओर धकेल देता है।

यदि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें 'धोखे के रास्ते' को छोड़कर 'संवाद के सेतु' बनाने होंगे। हत्या किसी समस्या का अंत नहीं, बल्कि अपराधी के लिए स्वयं के विनाश की शुरुआत है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें रिश्तों में पारदर्शिता और नैतिकता की वह नींव फिर से बनानी होगी, जो प्रेम को कत्ल नहीं, बल्कि जीवन जीने का आधार बनाए। यह सुधार किसी एक संस्था या व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है; इसके लिए घर, समाज, शिक्षा और कानून को एक साथ मिलकर काम करना होगा। यह समय है कि हम रिश्तों की डोर को पुनः अपनी संस्कृति और संस्कारों की मजबूती प्रदान करें, ताकि भविष्य में 'अग्नि' केवल पवित्रता की साक्षी बने, विनाश की नहीं। समाज को उन मनोवैज्ञानिक संकेतों को समझने की जरूरत है जो एक सामान्य व्यक्ति को अपराधी बना देते हैं। जब हम अपने पड़ोस, परिवार और मित्रों के प्रति अधिक जागरूक और सहायक होंगे, तो शायद हम उन घटनाओं को होने से पहले ही रोक सकें। अंततः, एक सभ्य समाज का माप इस बात से नहीं होता कि वह अपराधियों को कितनी कड़ी सजा देता है, बल्कि इस बात से होता है कि वह अपराध को पैदा होने से पहले ही रोकने में कितना सक्षम है।

शिक्षा

डॉ. रजनीश

(लेखिका पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल में सहायक ग्रंथालय हैं)

स्किल्ड युवाओं की जरूरत है समाज को

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अस्तित्व में आते ही भारत में मैकाले की डिग्री शिक्षा के स्थान पर कौशल उन्नयन ने जगह बना ली है। वर्षों से डिग्री शिक्षा ने बेरोजगारों की फौज खड़ी की है। उनके हाथों में उच्च अंकों की मार्कशीट तो जरूर है लेकिन उनके पास कोई स्कील नहीं होने के कारण वे स्वयं को किसी खास ट्रेड में दक्ष नहीं कर पा रहे हैं। इस दृश्य को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समझा और करीब साढ़े तीन दशक बाद शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर शिक्षा को कौशल से जोड़ कर युवाओं में आत्मविश्वास का संचार किया है। मध्यप्रदेश की चर्चा करें तो हमने भी कौशल उन्नयन में केन्द्र सरकार की अनुगामी बनकर युवाओं को स्कील से जोडक़र उज्जवल भविष्य दे सकें। उन्हें निराशा और कुंठा से बाहर निकाल सकें। यही कारण है कि हम प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई को कौशल उन्नयन दिवस मनाते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य है कि युवाओं को प्रेरित करें कि वे अक्षर ज्ञान से आगे निकल कर स्वयं को स्कील्ड बनाएं। ये नए भारत के युवा हैं जिनके पास शिक्षा के साथ स्कील है और जो नौकरी के मोहताज नहीं बल्कि स्वयं कुछ कर दिखाने के लिए बेताब हैं।

बदलती दुनिया और नई जरूरतें आज के दौर तकनीक का है। आपने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' या रोबोट जैसी चीजों के बारे में जरूर सुना होगा। मोबाइल ऐप और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हर दिन बदल रहे हैं। ऐसे में जो काम लोग पहले हाथों से या पुराने तरीकों से करते थे, वे अब कंप्यूटर से चुटकियों में हो जाते हैं। इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। अब पुराने ढर्रे पर बैठकर काम नहीं चलाया जा सकता। हर साल 'कौशल उन्नयन दिवस' मनाने का सीधा मकसद यही है कि हम अपनी पुरानी सोच को बदलें और यह समझें कि आज के दौर में केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि हाथों में कोई न कोई हुनर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। डिग्री और हुनर का फर्क साधारण शब्दों में कहें तो डिग्री आपको यह बताती है कि आपने क्या पढ़ा है, लेकिन कौशल यह तय करता है कि आप क्या 'कर' सकते हैं। पुराने समय में माना जाता था कि अगर किसी ने अच्छे नंबरों से बीए, बीएससी या इंजीनियरिंग कर ली, तो उसकी जिंदगी संवर गई। लेकिन आज समय बदल चुका है। कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से काम करने के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। आज कंपनियों को ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुरंत काम संभाल सकें, जिन्हें कंप्यूटर चलाना आता हो, जो अच्छी बातचीत जिसे कम्युनिकेशन स्कील कहते हैं, कर सकें। अगर आपके पास डिग्री है लेकिन काम की व्यावहारिक समझ नहीं है, तो आज के बाजार में टिकना मुश्किल है।

हम खुद को समय के साथ अपडेट नहीं करेंगे, तो हम पीछे छूट जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज के दौर में कीपैड वाले पुराने मोबाइल फोन पीछे छूट गए हैं। हर वर्ग के लिए जरूरी है हुनर कौशल विकास का मतलब सिर्फ कंप्यूटर सीखना या दफ्तर में काम करना नहीं है। जब गांव या शहर की महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, अचार-पापड़ बनाने, ब्यूटी पार्लर चलाने या डिजिटल पैमेंट संभालने का हुनर सीखती हैं, तो वे अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। इससे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरती है। एक साधारण दुकानदार भी अगर ऑनलाइन पेमेंट लेना, सोशल मीडिया पर अपने सामान का प्रचार करना सीख ले, तो उसका व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। यह भी कौशल उन्नयन का ही एक हिस्सा है। 'स्किल इंडिया' जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां मुफ्त या बहुत कम फीस में अलग-अलग काम सिखाए जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज में एक बड़ी कमी है–हम शारीरिक श्रम या तकनीकी काम (जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक) को क्लर्क या दफ्तर की नौकरी से छोटा समझते हैं। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। दुनिया के विकसित देशों (जैसे जर्मनी या जापान) में हुनरमंद लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान और पैसा मिलता है। जब तक हम हुनर की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इस संदर्भ में यह बताना जरूरी है कि जान लें कि मध्यप्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल शिक्षार्थियों के लिए एक इंटरैक्टिव सीखने का माहौल बनाता है और जुनून पैदा करता है व्यावसायिक शिक्षा। यह विभिन्न माध्यमों से रुचियों और प्रतिभाओं को विकसित करने के अवसर भी प्रदान करता है पाठ्येतर गतिविधियां। प्रत्येक कक्षाओं और प्रयोगशाला को विशेष सुविधाओं के साथ बनाया गया है विभिन्न व्यावसायिक विषयों के प्रशिक्षुओं के लिए ताकि वे जानकारी और व्यावहारिक कौशल हासिल कर सकें उनके चुने हुए क्षेत्र।

बदलती दुनिया और नई जरूरतें आज के दौर तकनीक का है। आपने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' या रोबोट जैसी चीजों के बारे में जरूर सुना होगा। मोबाइल ऐप और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हर दिन बदल रहे हैं। ऐसे में जो काम लोग पहले हाथों से या पुराने तरीकों से करते थे, वे अब कंप्यूटर से चुटकियों में हो जाते हैं। इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। अब पुराने ढर्रे पर बैठकर काम नहीं चलाया जा सकता। हर साल 'कौशल उन्नयन दिवस' मनाने का सीधा मकसद यही है कि हम अपनी पुरानी सोच को बदलें और यह समझें कि आज के दौर में केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि हाथों में कोई न कोई हुनर होना सबसे ज्यादा जरूरी है।

कहने का अर्थ यह कि हम युवाओं को कौशलपूर्ण बनाने का उपक्रम करते हैं।

कौशल उन्नयन कोई मुश्किल या भारी-भरकम सरकारी नीति नहीं है, बल्कि यह हर आम इंसान की जरूरत है। यह हमें सिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे आप छात्र हों, नौकरीपेशा हों या घरेलू महिला–हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह सकती है, लेकिन आपका हुनर एक ऐसी चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। आइए, इस कौशल उन्नयन दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने भीतर छिपे हुनर को पहचानेंगे और उसे और बेहतर बनाएंगे।

विश्व युवा कौशल दिवस विशेष

विनोद कुमार विक्की

स्वतंत्र टिप्पणीकार

साझा भविष्य के लिए युवा भारत की चुनौती

भारत में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल का प्रतिशत लगभग 5.4 प्रतिशत है, जबकि चीन, जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह कई गुना अधिक है। यह अंतर केवल आँकड़ों का नहीं, बल्कि उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास का भी है। भारत में बड़ी संख्या में युवा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ उन्हें न तो व्यवस्थित प्रशिक्षण मिलता है और न ही कौशल उन्नयन के पर्याप्त अवसर। इस समस्या के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, जो लंबे समय तक डिग्री-केंद्रित रही है।

विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि यह युवा शक्ति आधुनिक कौशल, तकनीकी दक्षता और नवाचार से संपन्न होगी तो भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। किंतु यदि यही युवा वर्ग पर्याप्त कौशल और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण से वंचित रह गया, तो बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष जैसी समस्याएँ और गंभीर हो सकती हैं। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व युवा कौशल दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित कर 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी तथा व्यावसायिक कौशलों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 2026 की थीम 'साझा भविष्य के लिए कौशल' इस विचार को रेखांकित करती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वचालन, रोबोटिक्स और डिजिटल परिवर्तन के इस युग में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। भविष्य की अर्थव्यवस्था में वही युवा सफल होंगे, जिनके पास तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक, डिजिटल, संचार, समस्या-समाधान और नवाचार संबंधी कौशल भी होंगे।

भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना तथा माई भारत जैसे अनेक कार्यक्रम युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं। समय-समय पर रोजगार मेले, करियर परामर्श शिविर, डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उद्योगों के सहयोग से कौशल उन्नयन की पहल भी की जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए भी तैयार करना है।

इन प्रयासों के बावजूद वास्तविक स्थिति अभी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल का प्रतिशत लगभग 5.4 प्रतिशत है, जबकि चीन, जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह कई गुना अधिक है। यह अंतर केवल आँकड़ों का नहीं, बल्कि उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास का भी है। भारत में बड़ी संख्या में युवा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ उन्हें न तो व्यवस्थित प्रशिक्षण मिलता है और न ही कौशल उन्नयन के पर्याप्त अवसर।

इस समस्या के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, जो लंबे समय तक डिग्री-केंद्रित रही है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में सैद्धांतिक ज्ञान पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जाता है, जबकि उद्योगों की आवश्यकता व्यावहारिक दक्षता, तकनीकी समझ और कार्यकुशलता की होती है। परिणामस्वरूप लाखों स्नातक डिग्री लेकर रोजगार की तलाश में भटकते हैं, जबकि उद्योगों को योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिल पाते। यही कारण है कि देश में एक ओर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी ओर कुशल मानव संसाधन की कमी बनी हुई है।

दूसरी बड़ी चुनौती डिजिटल असमानता है। महानगरों और बड़े शहरों के युवाओं को आधुनिक तकनीक, इंटरनेट और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों की अपेक्षाकृत बेहतर सुविधा उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में आज भी डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी संसाधनों का अभाव है। इससे अवसरों में असमानता बढ़ती है और बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवा अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते।

तेजी से विकसित होती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और स्वचालन ने रोजगार की प्रकृति भी बदल दी है। अनेक पारंपरिक नौकरियाँ समाप्त हो रही हैं, जबकि नई प्रकार की नौकरियाँ सामने आ रही हैं। अब केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है; लगातार सीखने, नई तकनीकों को अपनाने और समय के अनुसार स्वयं को अपडेट करने की क्षमता भी आवश्यक हो गई है। भविष्य का कार्यस्थल बहु-कौशल और पुनः-कौशल की मांग करेगा।

कौशल विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और समाज को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। उद्योगों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के निर्माण में सहयोग देना चाहिए ताकि प्रशिक्षण रोजगार बाजार की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। विद्यालय स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय जागरूकता और उद्यमिता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। साथ ही, युवाओं में नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और आत्मनिर्भरता की भावना को भी प्रोत्साहित करना होगा।

भारत की युवा आबादी विश्व के लिए एक बड़ी संभावना है। यदि यह ऊर्जा सही दिशा, उचित प्रशिक्षण और आधुनिक कौशल प्राप्त कर लेती है, तो भारत केवल दुनिया का सबसे युवा देश ही नहीं, बल्कि सबसे सक्षम और उत्पादक राष्ट्र भी बन सकता है। इसके विपरीत यदि कौशल और रोजगार के बीच की खाई बनी रही, तो जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय बोझ में बदल सकता है।

अंततः, 'साझा भविष्य के लिए कौशल' केवल एक वार्षिक थीम नहीं, बल्कि भारत के विकास का रोडमैप है। आज आवश्यकता डिग्रियों की संख्या बढ़ाने से अधिक कौशल की गुणवत्ता बढ़ाने की है। जब शिक्षा, तकनीक, उद्योग और कौशल विकास एक साथ आगे बढ़ेंगे, तभी युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी सिद्ध होगी। भविष्य उन्हीं देशों का होगा, जो अपने युवाओं को केवल शिक्षित ही नहीं, बल्कि कुशल, नवाचारी और आत्मनिर्भर भी बनाएँगे।

आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त हुआ मकान

● कलेक्टर ने तत्काल सहायता के दिए निर्देश

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

बैतूल। कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम चिखलीमाल निवासी ललिता इवने ने आंधी-तूफान से अपना मकान क्षतिग्रस्त होने की व्यथा कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि तेज आंधी और तूफान के कारण उनका मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे परिवार के सामने सुरक्षित आवास का संकट खड़ा हो गया है। ललिता इवने की पीड़ा सुनकर कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने तत्काल तहसीलदार घोड़ाडोंगरी से प्रकरण की जानकारी ली। तहसीलदार ने बताया कि मकान क्षति का आकलन कर आर्थिक सहायता के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया जा चुका है। इस पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने बिना विलंब किए शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने आवेदक की पीड़ा को देखते हुए रेडक्रॉस मद से भी तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदिका की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता की जांच कर, पात्र पाए जाने पर उन्हें आवास सहायता का लाभ भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई में दोबारा न आना पड़े। इस दौरान अपर कलेक्टर वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

पारसडोह डैम की पाइपलाइन के सुधार के दिए निर्देश - जनसुनवाई में प्रभातपट्टन के ग्राम देवभिलाई निवासी बाया लिखितकर की वसीयत में दी गई भूमि पर कब्जा नहीं लेने देने की समस्या पर कलेक्टर ने सुनवाई कर तहसीलदार प्रभातपट्टन को निराकरण के निर्देश दिए। मुलताई के ग्राम सिपाहा के डुमरिया पवार की आबादी भूमि के कच्चे मार्ग की चौड़ीकरण किए जाने के आवेदन पर तहसीलदार मुलताई को मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। आठनेर निवासी मृदुल जायसवाल ने पारसडोह डैम की पाइपलाइन के समस्या का समाधान किए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने डब्ल्यूआरडी ईई मुलताई को आवेदक की समस्या के समाधान के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़वाने सौंपा आवेदन - ग्राम सातलदेही निवासी रमेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास में नाम न होने के आवेदन पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी सीईओ को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम बिहरगांव निवासी निर्मल सिंह तोमर ने बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को जांच कर आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम गंगापुर निवासी नत्थू द्वारा स्वीकृत मुआवजा राशि दिलाने के आवेदन पर कलेक्टर ने मुलताई एसडीएम को जांच कर आवेदक की समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

एबीवीपी ने छात्राओं से छेड़छाड़ और पथराव का लगाया आरोप

● असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग

बैतूल। जेएच कॉलेज में आयोजित नवागंतुक विद्यार्थी सम्मेलन के बाद हुए कथित विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गंज थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद असामाजिक तत्वों ने परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और पथराव भी किया तथा जान से मारने की धमकी दी। परिषद ने दोषियों के विरुद्ध तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर छात्र हितों की रक्षा के लिए परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गंज थाना प्रभारी को दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार 13 जुलाई को जेएच कॉलेज में नवागंतुक विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। परिषद का आरोप है कि कार्यक्रम के समापन के बाद कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने परिषद के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। शिकायत में आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने छात्रा कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस दौरान अभाविप कार्यकर्ता दीपेंद्र पठाड़े गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर पर पत्थर लगने से फ्रैक्चर होने की बात शिकायत में कही गई है। एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र एवं शिकायतकर्ता लक्की खातरकर ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने रोशन कोसे और साहिल शेख के साथ भी गाली-गलौज की तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शिकायती पत्र में घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए आरोपियों के विरुद्ध तत्काल और ठोस कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में फिलहाल बैतूलगंज थाना पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। परिषद ने कॉलेज परिसर और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की भी मांग की है।

सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम

● सांदीपनि विद्यालय प्राचार्य की अनूठी पहल

बैतूल/घोड़ाडोंगरी। सांदीपनि विद्यालय घोड़ाडोंगरी में छात्र/छात्राओं के जन्मदिन पर प्रार्थना सभा में अभी तक उन्हें ग्रीटिंग कार्ड भेंट कर शुभकामनाएं संदेश चॉकलेट वितरित किए जाते थे, लेकिन बालसभा में अब सांदीपनि विद्यालय के प्राचार्य, छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों की अनूठी पहल से छात्रों एवं शिक्षकों के जन्मदिन अवसर पर एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करने से पर्यावरण एवं स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। एक पेड़ लगाए और अपने आसपास के वातावरण को हरा-भरा बनाने को लेकर अभिभावकों एवं आम जनमानस से अपील कि परिवार के सदस्यों के जन्मदिन अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाए एवं प्रकृति को हराभरा बनाये। सांदीपनि विद्यालय के प्राचार्य विवेक तिवारी ने कहा कि पर्यावरण के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती आइए हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करे,प्रकृति के साथ प्रेम और संतुलन बनाए ।सांदीपनि विद्यालय की छात्रा कीर्ति भुजवरे, जाह्नवी चौरे ने कहा कि पर्यावरण को हराभरा बनाने हम सभी छात्र अपने जन्मदिन पर शाला परिसर में एक पौधारोपण कर उसकी देखभाल की समुचित व्यवस्था भी करेंगे साथ ही शिक्षक भी जन्मदिन पर पौधारोपण कर धरती को हराभरा बनाएंगे ।गौरतलब हो कि सांदीपनि विद्यालय घोड़ाडोंगरी के पर्यावरण को लेकर अनूठी पहल से शाला परिसर ही नहीं आसपास का वातावरण भी हराभरा होगा ।क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों,गणमान्य नागरिकों सहित अभिभावको ने अनूठी पहल पर प्रसन्नता व्यक्त की एवं सहयोग का आश्वासन भी दिया है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जिले में हुआ व्यापक पौधरोपण

बैतूल। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न विकासखंडों में व्यापक स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र का विस्तार तथा जनसामान्य को वृक्षारोपण एवं पौधों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना रहा। विकासखंड बैतूल की ग्राम पंचायत कढ़ाई स्थित कढ़ाई देव पहाड़ी पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती पुष्पा झरबड़े की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का समन्वयन मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री संतोष सिंह राजपूत द्वारा किया गया। इस अवसर पर नवांकुर संस्था भूपेंद्र ग्रामोत्थान महिला एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र मालवीय सहित जीवनलाल, श्यामराव देशमुख, मुन्नालाल यादव, धनराज रावत, विष्णु घेरकी, राजन यादव, नीलम कड़वे, शिवपाल यादव, गोकुल यादव तथा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कढ़ाई के सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इसी श्रृंखला में विकासखंड घोड़ाडोंगरी के ग्राम घुग्गी कान्हावाड़ी में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कान्हावाड़ी द्वारा 100 महुआ के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र उइके, जोधा धुर्वे, रामशंकर गोहे, सुखलाल धुर्वे, परिषद के परामर्शदाता जतिन प्रजापति एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं विकासखंड आठनेर में ÷एक पेड़ मां के नाम÷ अभियान के अंतर्गत सातनेर सेक्टर के ग्राम टेमनी में समिति एवं नवांकुर संस्था तासी प्रभास नागरिक सेवा समिति द्वारा 11 फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विकासखंड समन्वयक मधु चौहान ने आगामी वर्षा ऋतु में ग्राम में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने की योजना पर चर्चा की तथा ग्रामीणों से अधिकाधिक पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण का आह्वान किया। सभी स्थानों पर कार्यक्रम के दौरान सहभागियों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण कर पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर उनकी नियमित देखभाल करने का संदेश दिया। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित एवं संतुलित पर्यावरण के निर्माण का जनआंदोलन है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और स्थायी पहल सिद्ध होगी।

नमस्ते सेलिब्रेशन में स्वच्छता कर्मियों को मिली सुरक्षा सामग्री

● भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वच्छता कर्मियों का किया सम्मान

बैतूल। नगर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वच्छता कर्मियों के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नमस्ते सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें मास्क, सेफ्टी किट, सुरक्षा जूते और टोपी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता कर्मियों के समर्पण की सराहना करते हुए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम बैतूल विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पर्वतीबाई बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षा सामग्री वितरित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया गया कि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की सुरक्षा सामग्री की आवश्यकता होगी तो वे नगर पालिका कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकेंगे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों के अथक परिश्रम और समर्पण से ही शहर स्वच्छ एवं स्वस्थ बना रहता है। उनके योगदान का सम्मान करना और उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में संतोष धनोलिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल आयोजन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों के सहयोग से संपन्न हुआ।

3 दिन तक जिले के पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे

बैतूल। मप्र पटवारी संघ प्रांतीय आह्वान पर तथा पटवारियों की वर्षों पुरानी लंबित मांगों एवं मुख्यमंत्री द्वारा पटवारी महासम्मेलन में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की मांग को लेकर जिला के समस्त पटवारी आज बुधवार से 17 जुलाई तक तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मंगलवार को जिले की तहसील अध्यक्षों एवं पटवारियों द्वारा संबंधित तहसीलदारों को सामूहिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की सूचना दी है। इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष मोहनलाल धुर्वे ने बताया कि प्रदेश संगठन द्वारा 8 जुलाई 2026 को दिए गए ज्ञापन के समर्थन में जिले के सभी पटवारी एकजुट होकर 15 से 17 जुलाई तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पटवारियों की लंबित एवं न्यायोचित मांगों के प्रति शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। श्री धुर्वे ने बताया कि जिले के सभी पटवारी संघ के आह्वान के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इस सामूहिक अवकाश में सहभागी होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शासन शीघ्र ही पटवारियों की वर्षों पुरानी मांगों, वेतन विसंगतियों, तकनीकी समस्याओं एवं अन्य सेवा संबंधी मुद्दों का सकारात्मक समाधान करेगा।

पुष्य नक्षत्र पर स्वर्ण प्राशन आज

आयुर्वेद चिकित्सालय टिकारी में बीएमडी जांच शिविर और स्वर्ण प्राशन का आयोजन

बैतूल। आयुष विभाग द्वारा आज बुधवार 15 जुलाई को शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय टिकारी में निःशुल्क बीएमडी जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन पुष्य नक्षत्र के अवसर पर जिले के चार आयुष केंद्रों पर 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। विभाग ने जिलेवासियों से इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने बताया कि बीएमडी जांच शिविर का आयोजन धूतपापेश्वर के सौजन्य एवं सहयोग से किया जा रहा है। बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) टेस्ट हड्डियों की मजबूती और घनत्व का आकलन करने वाली महत्वपूर्ण जांच है, जिसके माध्यम से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया जैसी बीमारियों का समय रहते निदान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पुष्य नक्षत्र के अवसर पर आयुष विभाग द्वारा स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय टिकारी, जिला चिकित्सालय आयुष विंग बैतूल, शासकीय आयुर्वेद औषधालय गर्ग कॉलोनी तथा शासकीय आयुर्वेद औषधालय भैंसदेही में आयोजित किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने वार्षिक निरीक्षण के साथ किया पौधरोपण

सोहागपुर। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साईं एस कृष्ण छोटा ने नवीन पुलिस थाना परिसर में वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री साईं एस कृष्ण छोटा का नवीन पुलिस थाना परिसर में आगमन पर एसडीओ पुलिस संजू चौहान ने गुलदस्ता भेंटकर करके स्वागत किया । इसी अवसर पर सोहागपुर पुलिस स्टाफ ने पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साईं एस कृष्ण छोटा को सलामी दी ।इसके उपरांत एसपी ने परेड का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान आपने स्टाफ से बातचीत की। पुलिस अधीक्षक श्री साईं कृष्ण एस थोटा ने बताया कि यह रोटीन निरीक्षण है। जिसमें वार्षिक निरीक्षण करके दस्तावेजों का रखरखाव, कार्य करने की पद्धति, जवानों का अनुशासन आदि की जानकारी ली जाती है। पुलिस अधीक्षक श्री साईं एस कृष्ण छोटा ने वॉलीबॉल ग्राउंड एवं क्रिकेट प्रैक्टिस ग्राउंड का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसी अवसर पर आपने एक वृक्ष मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया गया।

विकास का सर्मथन, लेकिन चार, छै,बारह महीने में सड़क उखड़ने लगे यह जनता-जनार्दन के पैसों का दुरुपयोग: धर्मदास बैलवंशी

सोहागपुर। कई सालों के बाद सोहागपुर नगर पंचायत परिषद में भाजपा काबिज हुई है। लेकिन प्रारंभ से इस नगर पंचायत परिषद पर उंगली उठने लगी थीं । विपक्ष में रहकर भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस के पार्षद उठाए तो यह उनका नेतिक कर्तव्य बनता है। लेकिन विगत दिनों जब भाजपा के पार्षद पति एवं पूर्व नपाध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं भाजपा युवा मोर्चे की सोशल मीडिया पर नोक झोंक तथा उस पर पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष की भ्रष्टाचार पर टीका-टिप्पणी से कहीं न कहीं भाजपा की छवि जनता-जनार्दन में खराब हो रही है। भाजपा नेतृत्व को इस पर रोक लगानी चाहिए। अन्यथा आगामी चुनावों इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है?। वहीं यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल के नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में किस किसने घात किया था। वहीं यह भी परिलक्षित है कि बीते विधानसभा चुनाव में भी यदि किसी डिटेक्टिव एजेंसी के माध्यम से जांच कराई जाए तो अपने ही साथ साथ चलने वाले कठघरे में खड़े नजर आएंगे। हाल ही में क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई है। क्षेत्रीय विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद धर्मदास बैलबंशी ने विकास सर्मथन करते आगाह किया है कि हम दलगत राजनीति से हटकर विकास कार्यों का समर्थन करते है। सड़क के भूमि पूजन का स्वागत है। श्री बैलवशी ने सोहागपुर के नागरिकों को सोशल मीडिया पर आगाह करते लिखा है कि नगर पंचायत परिषद ने जिस मान से जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया है ।उसी मान से नगर पंचायत परिषद घटिया तरह के गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कर रही है। आपने आरोप लगाया है कि लाखों रूपये से बनी। 1. रेलवे स्टेशन से जयमल सिंह कालोनी तक डामर रोड सड़क एक बरसात भी नहीं झेल सकी और उखाड़ गई। 2. स्वागत द्वार निर्माण के महज करीबन 20 दिनों में ही पत्थर टूटकर गिरने लगे। वहीं श्री बेल बंशी ने। 3. राजेंद्र वार्ड में बिहारी चौक से लेकर मज्जिद तक बनी सड़क के गुणवत्तापूर्ण कार्य की सराहना भी की है। लेकिन शेष शास्त्री वार्ड,रामप्रसाद वार्ड, रामगंज वार्ड, तिलकवार्ड में बनी समस्त सड़कें एक वर्ष में ही फटने लगी हैं ।गिट्टी निकलने लगी है। आपने कहा जनता को गड्ढेदार सड़कें क्यों दी जा रही है। वहीं आपने नगर पंचायत अध्यक्ष की तारीफ करते कहा है उनकी इच्छा शक्ति तो निर्माण कार्य में गुणवत्ता प्रदान करने की नजर आती है। राजेंद्र वार्ड पार्षद और अध्यक्षा महोदया की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि राजेंद्र वार्ड की रोड में गुणवत्ता पूर्ण नजर आ रही है। श्री बेल बंशी ने आरोप लगाया है राजेन्द्र वार्ड पार्षद गौरव पालीवाल के सामने कमीशन साथी की एंट्री करने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। इसी कारण उक्त सड़क बेहतर बनी है। आप आगे कहते हैं कि सोहागपुर की जनता के लिए सोचनीय विषय है ।कि जिस ठेकेदार ने राजेंद्र वार्ड की रोड बनाई थी । उसी ठेकेदार ने अन्य वार्डो की सड़कें बनाई हैं । राजेंद्र वार्ड छोड़कर अन्य वार्डो की सड़के क्यों फटने लगी? क्यों गिट्टी निकलने लगी। वहीं वरिष्ठ पार्षद धर्मदास बैलबंशी सोशल मीडिया पर मंझले मंझले कहकर कटाक्ष कर रहे हैं। सोहागपुर की जनता-जनार्दन समझ नहीं पा रही है वह किरदार कार मंझले कौन हैं। जो तृणमूल कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों जैसा व्यवहार जनता के साथ कर रहे हैं। इस प्रतिनिधि ने श्री बैलवशी से उनके नाम का खुलासा करने को कहा लेकिन उन्होंने कहा इसे राज ही रहने दो।ऊपर वाले सब जानते हैं।

अनुकरणीय पहल

आदिवासी ग्राम सेहरा ग्राम पंचायत ने दिया शराबबंदी का प्रस्ताव, ज्ञापन सौंपा

सोहागपुर । विगत दिवस आदिवासी ग्राम सेहरा में ग्राम पंचायत टेकापार तहसील सोहागपुर के समस्त ग्रामवासी महिला एवं पुरुष की बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में शराब के दुष्परिणामों के विषय में चर्चा की गई। जिसमें कई महिलाओं एवं नागरिकों ने अपने अपने विचार रखे। अंत में समस्त ग्राम वासियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समय एवं परिस्थिति को देखते हुए महुआ शराब बनाना एवं बेचना बंद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में महुआ की शराब काफी लम्बे समय से प्रचलन में है। इसी समय बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम सभा के नियम एवं निर्णय का पालन नहीं करता है ।ऐसी स्थिति में उसके प्रति पुलिस कार्रवाई कराई जाएगी। अतः हम समस्त ग्रामवासी महिला एवं नागरिक चाहते हैं ।कि शासन प्रशासन पंचायत में लिए गए निर्णय प्रस्ताव पर अमल कराने में हमें सहयोग प्रदान करें। ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति थाना प्रभारी , अनुविभागीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परिषद को प्रदान की गई। उल्लेखनीय बात यह रही कि सोहागपुर पुलिस थाने परिसर में आदिवासी महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा।

विदिशा जिले की 2.71 लाख लाड़ली बहनों के खातों में अंतरित किए 40 करोड़ रुपये

विदिशा (निप्र)। डॉ. मोहन यादव जी के द्वारा आज भिंड जिले से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत माह जुलाई 2026 की आर्थिक सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की पात्र लाड़ली बहनों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण किया। इस अवसर पर विदिशा जिले की 2,71,446 लाड़ली बहनों के बैंक खातों में लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा के निर्देशन में आज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिलेभर के आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं नगरीय निकायों में सजीव (लाइव) प्रसारण कराया गया। बड़ी संख्या में लाड़ली बहनों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए मुख्यमंत्री का उद्बोधन देखा व सुना गया है।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने उपस्थित लाड़ली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार की एक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी पहल है। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो रही है तथा उनके परिवारों को भी संबल मिल रहा है।जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिले के सभी परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व से आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई थीं। सभी केन्द्रों पर हितग्राही महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सफल प्रसारण कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरण का लाइव प्रसारण देखा तथा प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। जिले के सभी विकासखंडों एवं नगरीय निकायों में कार्यक्रम उत्साह, उल्लास एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सम्पन्न हुआ।

संक्षिप्त समाचार

लाडली बहना योजना ने बढ़ाया आत्मविश्वास

मीना नामदेव बनीं आर्थिक रूप से सशक्त

विदिशा (निप्र)। विदिशा शहर के तलैया मोहल्ला निवासी 48 वर्षीय श्रीमती मीना नामदेव के जीवन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना नई उम्मीद लेकर आई है वे आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के रूप में कार्यरत हैं और अपनी आय से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सीमित आय के कारण कई बार घरेलू जरूरतों और छोटे-छोटे खर्चों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता था। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के प्रारंभ से ही वे नियमित रूप से लाभान्वित हो रही हैं। योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रतिमाह मिलने वाली 1500 रुपये की राशि उनके लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा साबित हो रही है। इस राशि से वे घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्री, सहित अन्य छोटे-छोटे खर्चों का आसानी से प्रबंध कर लेती हैं। श्रीमती मीना नामदेव का कहना है कि इस योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया है। अब वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के परिवार की जरूरतों में सहयोग कर पा रही हैं। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल है, जिसने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हुए उन्हें सम्मान और सुरक्षा का नया एहसास कराया है।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनी परिवार का सहारा

योजना के प्रारंभ से ही मिल रहा लाभ, प्रतिमाह मिल रही 1500 रुपये की राशि

विदिशा (निप्र)। विदिशा शहर के टीला खेड़ी क्षेत्र की 25 वर्षीय श्रीमती शिवानी शिल्पकार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से प्रारंभ से ही लाभान्वित हो रही हैं। वे आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनके पति इलेक्ट्रिशियन हैं। दोनों अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। उनका एक बेटा है, जो विद्यालय में अध्ययनरत है। श्रीमती शिवानी बताती हैं कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली 1500 रुपये की आर्थिक सहायता से उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों और घरेलू खर्चों को पूरा करने में काफी सहारा मिला है। इससे परिवार का आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और वे अपने बच्चे की शिक्षा तथा दैनिक आवश्यकताओं पर भी बेहतर ढंग से खर्च कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने महिलाओं को आर्थिक संबल देने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि यह योजना उनके जैसे अनेक परिवारों के लिए राहत और सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है।

मानसून की पहली बारिश में गोराखाल झरना बना सैलानियों का ठिकाना

हरदा(निप्र)। मानसून की पहली बारिश के साथ जिले का प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर है। सतपुड़ा की वादियों में रहटगांव वन परिक्षेत्र का गोराखाल झरना इन दिनों सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वीकेंड पर हरदा सहित आसपास के जिलों से सैकड़ों प्रकृति प्रेमी यहां पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। जंगल के रास्तों से झरने तक पहुंचने का सफर एडवेंचर पसंद करने वालों को रोमांचित कर रहा है। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। बारिश के कारण चट्टानों पर फिसलन बढ़ गई है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पानी के तेज बहाव में न उतरें। गहरे कुंड से दूरी बनाए रखें। सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की गई है।

उच्च शिक्षा मंत्री परमार आष्टा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए

सीहोर (निप्र)। आष्टा में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने एक निजी क्लीनिक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने फीता काटकर क्लीनिक का उद्घाटन किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह क्लीनिक क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का दायित्व केवल उपचार करना ही नहीं, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। इस अवसर पर आष्टा विधायक श्री गोपाल सिंह इंजिनियर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने किया पौधरोपण

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शुक्रवार को उप तहसील कार्यालय बोरदेही परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर अमला एसडीएम श्री शैलेंद्र बड़ोनिया, नायब तहसीलदार रिचा कौरव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

जनसंख्या नियंत्रण और बच्चों के विधिक अधिकारों पर जागरूकता शिविर आयोजित

हरदा (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में 'विश्व जनसंख्या दिवस' के अवसर पर शनिवार को ए.डी.आर. सेन्टर, हरदा में माइंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश व सचिव श्री चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थित बच्चों को बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है।

भारत वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 146 करोड़ से अधिक है। देश की बड़ी आबादी में युवाओं की संख्या महत्वपूर्ण है, जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की बड़ी शक्ति बन सकती है। शिविर के दौरान विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि जागरूक नागरिक बनकर वे समाज में जनसंख्या नियंत्रण, लैंगिक समानता, शिक्षा के प्रसार तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों को पॉक्सो अधिनियम, बच्चों से संबंधित अन्य विभिन्न कानून जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 आदि के बारे में विस्तृत जानकारियां प्रदान की गई तथा बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लवकेश सिंह ने बच्चों को भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका के बारे में जानकारी दी। शिविर के दौरान बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं- निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता, नालसा पोर्टल, टोल फ्री नंबर 15100 आदि की भी जानकारी दी गई। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री एस.के. भदकारिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे, छात्र/छात्राएं, पैरालीगल वॉलेंटियर्स सहित लगभग 50 लोग उपस्थित रहे।

100% मूंग खरीदी की मांग पर किसानों का आंदोलन

सिवनी मालवा में अनिश्चितकालीन धरना, सुंदरकांड पाठ किया

सिवनी मालवा(निप्र)। सिवनी मालवा में भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। तहसील कार्यालय के सामने ग्रीष्मकालीन मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी सहित विभिन्न मांगों को लेकर यह आंदोलन चौथे दिन में प्रवेश कर गया। किसानों ने रविवार रात धरना स्थल पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस धार्मिक आयोजन में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसानों ने भगवान हनुमान से प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करने और सरकार को उनकी लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार ग्रीष्मकालीन मूंग की 100 प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय नहीं लेती, तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों की अन्य प्रमुख मांगों में खाद वितरण व्यवस्था में सुधार और ई-टोकन प्रणाली को समाप्त करना शामिल है। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके तहत किसान तहसीलदार को ट्रैक्टरों की चाबियां सौंपने और पैदल भोपाल कूच करने जैसे कदम उठा सकते हैं। सुंदरकांड पाठ के बाद, किसानों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में संकल्प लिया। उन्होंने दोहराया कि वे अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

स्पॉन्सरशिप योजना बनी नन्हीं 'आर्या' (परिवर्तित नाम) के भविष्य का सहारा

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के विकासखंड ग्यारसपुर अंतर्गत ग्राम गुलाबगंज की रहने वाली 'आर्या' (परिवर्तित नाम) ने कम उम्र में ही अपने माता-पिता को खो दिया। इस दुःखद घटना के बाद उसका पालन-पोषण उसके दादा-दादी द्वारा किया जा रहा है। सीमित आय के कारण परिवार के लिए बालिका की शिक्षा, पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं का खर्च वहन करना कठिन हो रहा था। ऐसे समय में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना परिवार के लिए संबल बनकर सामने आई। वर्ष 2025 से आर्या को योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस सहायता से आर्या की शिक्षा, स्कूल की आवश्यक सामग्री, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से हो रही है। वर्तमान में वह केजी-2 कक्षा में अध्ययनरत है और पूरे उत्साह के साथ अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

अमरगढ़ वॉटरफॉल जा रहे 20 लोगों को लौटाया वापस

कलेक्टर ने वर्षाकाल में जोखिमपूर्ण स्थलों पर न जाने की नागरिकों से की अपील

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. के निर्देशानुसार वर्षाकाल में नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी वॉटरफॉल, डैम, जल पर्यटन स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी हैं। इन स्थानों पर वर्षा के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए राजस्व, वन, पुलिस तथा अन्य विभागों के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से रोका जा सके तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। कलेक्टर के निर्देशानुसार अमरगढ़, दिगंबर और कालियादेव वॉटरफॉल सहित इन सभी दुर्घटना संभावित स्थलों पर नागरिकों को जाने से रोकने के लिए इनके पहुंच मार्गों पर टीमें तैनात की गई हैं। टीम द्वारा अमरगढ़ वॉटरफॉल जा रहे 20 लोगों को प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी देकर वापस लौटाया गया। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करें। नागरिकों का जीवन एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्षाकाल में जिले के इन पर्यटन स्थलों पर सीहोर के साथ-साथ भोपाल से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने तथा सुरक्षित व्यवहार अपनाने की अपील की है।

सिविल कांट्रेक्टर का ड्राइवर ही निकला चोर

नर्मदापुरम में 5 लाख के लैपटॉप और कम्प्यूटर 1 लाख रुपए में बेंचे

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम शहर की पॉश रिवर व्यू कॉलोनी में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के आवास से लाखों रूपये के लैपटॉप, डेस्कटॉप चुराने के मामले में आरोपी को अरेस्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर का ड्राइवर ही चोरी का मुख्य आरोपी निकला। उसने चोरी छुपे घर से 8 लैपटॉप, 8 कंप्यूटर सिस्टम, विदेशी कंपनी की ढ़ाई लाख रुपए की हाथ घड़ी समेत अन्य सामान्य चुरा ले गया था।

इसके बाद 7 कम्प्यूटर सिस्टम एवं 5 लैपटॉप इंदौर में अपने परिचित आफताब खान निवासी खजराना (इंदौर) को बेच दिए थे।

वारदात के चार दिनों के भीतर कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी और चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया। मुख्य आरोपी वाजिद गुफरान सिद्दीकी (ड्राइवर) निवासी जहांगीराबाद, भोपाल (वर्तमान पता अग्निहोत्री कॉलोनी, नर्मदापुरम), आफताब खान, निवासी खजराना इंदौर को गिरफ्तार किया। जिनसे 11लाख रुपए कीमत के 8 कम्प्यूटर सिस्टम, 8 लैपटॉप, 01 राडो कंपनी की कलाई घड़ी, एलईडी टीवी, आरओ, इलेक्ट्रिक केतली, ट्रिमर समेत अन्य चोरी गया सामान जब्त किया।

काम से बाहर गए थे, लौटे तो सामान गायब मिला

फरियादी कपिल शर्मा रिवर व्यू कॉलोनी के फेज-2 स्थित मकान नंबर पी-124 में अपने दो साथियों के साथ किराए पर रहते हैं। यहीं से वे अपनी कंपनी का संचालन भी करते हैं। वे मोहासा स्थित कैंपा कोला (ग्रेनटेक) कंपनी के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। 6 जुलाई को वे अपने साथियों के साथ काम के सिलसिले में मोहासा गए थे। इसी दौरान चोरों ने सूने मकान में घुसकर कर्मचारियों के चार लैपटॉप, पांच डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, आरओ मशीन और ढाई लाख रुपए की महंगी घड़ी चोरी कर ली। जिसकी शिकायत उन्होंने 8 जुलाई 2026 कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी।

ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया

एसपी साई कृष्णा ने चोरी की इस वारदात में आरोपियों को पकड़ने और सामान बरामद करने वाले टीम को सराहना की। ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया और 10 हजार रुपए के इनाम देने की घोषणा की। कार्रवाई में कोतवाली थाना टीआई निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला के नेतृत्व में सउनि संजय रघुवंशी, प्रधान आरक्षक रितेश यदुवंशी, आरक्षक - पंकेश बघेला, अविनाशी हारोडे, अजमेश चंद्रोल,हरीश डिगरसे, भिक्कू यादव तथा साइबर सेल के आरक्षक दीपेश सोलंकी की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।

5 लाख रुपए का माल एक लाख में बेचा

पूछताछ में आरोपी वाजिद गुफरान सिद्दीकी ने बताया कि चोरी गए 7 कंप्यूटर सिस्टम एवं 5 लैपटॉप अपने परिचित आफताब खान, निवासी खजराना (इंदौर) को बेच दिए थे। जिसके बदले उसे एक लाख रुपए दिए। शेष 4 कंप्यूटर सिस्टम, 4 लैपटॉप, विदेशी राडो कंपनी की ढ़ाई लाख रुपए कीमत की घड़ी, एलईडी टीवी, आरओ, इलेक्ट्रिक केतली, ट्रिमर सहित अन्य सामान अपने घर में छिपाकर रखा था। चोरी गया यह माल बरामद : 8 कंप्यूटर सिस्टम, 8 लैपटॉप, 01 राडो कंपनी की कलाई घड़ी, एलईडी टीवी, आरओ, इलेक्ट्रिक केतली, ट्रिमर, अन्य चोरी गया सामान कुल मशरुका किमती लगभग 11 लाख रूपये

उज्जैन में नवोदय विद्यालय से लापता दोनों बच्चों के शव बरामद

उज्जैन (नप्र)। जिले के घट्टिया तहसील में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां के जवाहर नवोदय विद्यालय से सोमवार शाम लापता हुए दो छात्रों के शव मंगलवार को विद्यालय के पास स्थित तालाब से बरामद हुए। यहां एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर तालाब से शव बरामद किए हैं। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

सोमवार शाम को दोनों हुए थे गायब- दरअसल, नवोदय विद्यालय परिसर में परिजनों के साथ ही रहने वाले 15 वर्षीय प्रज्ञान और 14 वर्षीय रोशन बरेठा सोमवार शाम से गायब हो गए। परिजन और स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, देर रात से ही तलाश शुरू कर दी गई। सुबह पास ही के तालाब में प्रज्ञान का शव मिला।

तालाब से मिले दोनों के शव- इसके बाद तत्काल एसडीआरएफ को सूचना दी गई और तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां दोपहर को रोशन बरेठा का भी शव बरामद कर लिया गया। घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों छात्र विद्यालय परिसर से बाहर कैसे पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

विद्यालय स्टाफ के हैं बच्चे

मामले में घट्टिया थाना प्रभारी करण खोवाल ने बताया कि दोनों बच्चे विद्यालय स्टाफ के हैं। प्रारंभिक जांच में संभावना है कि दोनों सोमवार शाम करीब 6 बजे तालाब में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मामले की जांच जारी है।

वहीं, एसडीएम राजाराम करजरे का कहना है कि बच्चे कल शाम से गायब थे। परिजन विद्यालय परिसर में ही रहते हैं। पास के तालाब से एक बच्चे का शव दिखा। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर दूसरे बच्चे का शव बरामद कर लिया है। उज्जैन पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।

जबलपुर में हिंदू संगठन ने स्कूल में तोड़फोड़ की

महिला कार्यकर्ताओं ने खिड़कियों के कांच फोड़े, धर्म परिवर्तन के आरोप पर पुलिस से झड़प

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के सेंट एलॉयसियस स्कूल में धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर मंगलवार दोपहर बड़ा हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्कूल परिसर में पहुंच गए और अंदर जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल में काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जो कर्मचारी धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है।

कर्मचारियों की शिकायत के बाद पहुंचे कार्यकर्ता- प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कुछ कर्मचारियों ने इस मामले की शिकायत हिंदू संगठन से की थी। इसके बाद करीब 50 कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प हो गई। करीब एक घंटे तक परिसर में हंगामा चलता रहा।

कर्मचारी बोला- चर्च जाकर पूजा करने का दबाव- स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी राजेश कुमार का कहना है कि वह पिछले 12 साल से इस स्कूल में काम कर रहा है। उसका आरोप है कि पिछले तीन महीने से उस पर रोज चर्च जाकर पूजा करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था।

उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिन भी काम पर बुलाया जाता था। राजेश का कहना है कि जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार किया, तो बिना किसी सूचना या नोटिस के उसे नौकरी से निकाल दिया गया।

मौके पर पहुंचा पुलिस बल

घटना की सूचना मिलते ही विजय नगर, माढोताल सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर प्रदर्शनकारियों को स्कूल परिसर से बाहर किया। प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी शिकायतें दोबारा मिलीं तो वे फिर आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान

सीएम मोहन बोले, जुए की लत जैसा है नशा करना

अवैध कारोबार, ड्रग माफिया के खिलाफ नरमी छोड़ गरमी से पेश आए पुलिस

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नशा ऐसे ही परिवार को बर्बाद करता है जैसे जुए की लत लगने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को बर्बाद कर देता है। पुलिस टीम समूचे रैकेट को पकड़ने के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार, ड्रग माफिया के खिलाफ नरमी छोड़ें और गरमी से पेश आएं।

हमने पुलिस को इसके लिए फ्री हैंड दिया है। हमारी सरकार अन्य राज्यों से हमारी सरकार तालमेल कर रही है। भावी पीढ़ी की सुरक्षा और समाज में जागृति के लिए एकजुट होकर काम करना है।

सीएम यादव ने ये बातें नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अभियान शुरू करने के दौरान कहीं। लाल सलाम के कारण स्मगलरों पर काम नहीं कर पा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने जो डेटलाइन दी थी, उसके पहले ही एमपी पुलिस ने लाल सलाम को खत्म करने का काम किया है।

प्रमोशन के कारण पुलिस के साथ सभी विभागों में उत्साह का माहौल बना है। ऐसे संस्कार युक्त सामाजिक अभियान का स्वागत करते हैं। नशा करने वालों के पुनर्वास का कार्यक्रम भी चल रहा है। 19 शहर और गांव में नशाबंदी का काम सरकार ने किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति के लिए रवीन्द्र भवन में मौजूद अफसरों, स्कूली छात्रों को शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के लिए सामाजिक न्याय विभाग काम कर रहा है। नशा नाश की जड़ है। नशा एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करता है। नशा करने वाले भी नशे से दूर होकर दूसरे नशा पीड़तों को नशा मुक्त करने का काम करते हैं। इनका सहयोग लिया जाता रहेगा।

पिछले साल चले अभियान के बाद ब्रिटेन की संसद ने किया था एमपी पुलिस का सम्मान- स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि 15 से 65 साल तक की उम्र के नागरिकों तक पुलिस पहुंचेगी और नशे के गंभीर दुष्प्रभाव की जानकारी देगी और बचने के उपाय बताने के लिए काम करेगी। सरकार की मंशा के अनुसार पिछले साल चलाए गए अभियान ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड में स्थान बनाया। ब्रिटेन की संसद में पिछले अभियान के बाद एमपी पुलिस को विशेष सम्मान दिया गया था।

नशे की लत से 33 करोड़ से अधिक दुनिया भर में पीड़ित हैं। 25 करोड़ लोग गांजे का नशा करते हैं। 6 करोड़ से अधिक लोग अफीम और अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसे काम के लिए संगठित गिरोह चलाने वालों पर कार्यवाही करना जरूरी है।

गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाल दी लकड़ी

अलीराजपुर में डकैती के बाद महिला के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी, चार गिरफ्तार

आलीराजपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले में 40 वर्षीय महिला के घर डकैती के दौरान उससे बर्बर सामूहिक दुष्कर्म पर बढ़ते जनाक्रोश के बीच पुलिस ने सोमवार को चार आरोपियों को हिरासत में लिया और घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश तेज कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

चार आरोपी हुए गिरफ्तार- अलीराजपुर एसपी रघुवंश कुमार सिंह ने बताया कि घटना के चार आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। उनके कब्जे से चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं, जिसे डकैती के बाद अपने साथ ले गए थे। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में मिले सुरागों के आधार पर लग रहा है कि आरोपियों की संख्या 10 के आस-पास हो सकती है और शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

डकैती के बाद किया गैंगरेप- एसपी ने बताया कि बोरी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में गत शुक्रवार की रात डकैती के दौरान आरोपियों ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसके निजी अंग में लकड़ी की एक चीज डाल दी थी। सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल महिला को इंदौर के एक सरकारी अस्पताल भेजा गया था।

महिला की स्थिति है ठीक- इंदौर स्थित अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत फिलहाल ठीक है और उसे जल्द ही छुट्टी दी जा सकती है। इस बीच, घटना पर आक्रोशित लोगों ने बोरी पुलिस थाने के सामने बड़ी तादाद में जुटकर धरना-प्रदर्शन किया।

दोषियों को फांसी देने की मांग- प्रदर्शनकारियों ने घटना के दोषियों को फांसी देने की मांग की और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। यह घटना राज्य के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान के गृह जिले में हुई। राज्य सरकार घटना को लेकर बेहद संवेदनशील है और इसके सभी दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस अधिकारियों से की बात- मंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है और आइंदा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस बीच, घटना की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति भी बोरी क्षेत्र में पहुंची। समिति के सदस्य और कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने दावा किया कि आलीराजपुर जिले की महिला के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी की गई।

लापता लड़कियों को ढूंढने में पुलिस गंभीर नहीं

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- जांच अधिकारियों को सिर्फ फेसबुक-इंस्टाग्राम का ही पता

ग्वालियर (नप्र)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य में लापता लड़कियों और गुमशुदा इंसानों की बरामदगी को लेकर पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है।

कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि पुलिस ऐसे मामलों को अत्यंत हल्के में ले रही है और जांच का जिम्मा ऐसे लापरवाह और अक्षम अधिकारियों को सौंप दिया जाता है, जिन्हें आधुनिक या प्रभावी तफ्तीश का ककहरा तक नहीं मालूम।

भिंड के आलमपुर थाने में दर्ज एक गुम इंसान मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं करने के केस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच सुनवाई कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने भिंड एसपी को वर्तमान जांच अधिकारी को तत्काल हटाने और मामले की कमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपने के कड़े निर्देश दिए हैं।

एएसआई बोले- इंस्टाग्राम-फेसबुक देख लिया, सुराग नहीं मिला- यह पूरा मामला भिंड जिले के आलमपुर थाने से जुड़ा है, जहां एक पिता ने अपनी लापता बेटी की बरामदगी के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डबल बेंच के समक्ष आलमपुर थाने में तैनात एएसआई ओंकार सिंह तोमर केस डायरी लेकर व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। कोर्ट ने जब उनसे लड़की की तलाश को लेकर किए गए प्रयासों पर सवाल दागे, तो एएसआई को जवाब देते नहीं बना। उन्होंने अदालत को बेहद गैर-जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि मैंने लड़की का इंस्टाग्राम और फेसबुक खंगाला है, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। वैसे, संदिग्ध को गांव में ही देखा गया था।

24 घंटे के भीतर जांच अधिकारी को हटाएं- इस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई और कहा कि विवेचना अधिकारी सिर्फ फेसबुक व इंस्टाग्राम तक ही सीमित हैं। एएसआई के इस जवाब पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि आईओ जांच करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। क्या पुलिस की तफ्तीश अब सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने तक सीमित रह गई है? बेंच ने सख्त संदेश देते हुए निर्देशित किया है।

- गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस उसे कतई हल्के में न ले। ● लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए हर संभव, वैज्ञानिक और गंभीर प्रयास किए जाएं। ● भिंड एसपी 24 घंटे के भीतर वर्तमान जांच अधिकारी को हटाएं। ● किसी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को केस सौंपें, जो अपनी पूरी ताकत लड़की को बरामद करने में झोंके।

भिंड एसपी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

हाईकोर्ट ने केवल निचले स्तर के अधिकारी को ही नहीं, बल्कि भिंड पुलिस अधीक्षक को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एसपी खुद जांच अधिकारियों की सक्षमता को परखे बिना ही लापरवाही से केस सौंप रहे हैं। अदालत ने भिंड एसपी से अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए 3 बिंदुओं पर जवाब तलब किया है।

मप्र में यूसीसी कमिटी ने सौंपी सीएम को रिपोर्ट

मोहन यादव ने कहा- कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखती

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में यूसीसी के लिए बनी कमिटी ने सीएम मोहन यादव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा मुझे यूसीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब कांग्रेस को भी इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या भोजशाला का, कांग्रेस हर विषय को केवल हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है। वहीं, सकारात्मक बात यह है कि सभी धर्मों के नागरिकों ने यूसीसी पर अपने विचार खुलकर और स्पष्ट रूप से रखे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना स्पष्ट रुख सामने नहीं रखा है। गौरतलब है कि सीएम मोहन यादव 14 जुलाई की सुबह विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने यहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व.कैलाश जोशी जी की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा की।

तीन खंडों में तैयार की गई रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने 13 जुलाई को अपना अंतिम प्रतिवेदन सौंपा। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर और सदस्य सचिव अजय कटेसरिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है। पहले खंड में समिति की अनुशंसाएं शामिल हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू विभिन्न कानूनों एवं परंपराओं का विश्लेषण करते हुए सुझाव दिए गए हैं। इस भाग में कुल 10 अध्याय शामिल हैं।

अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखने की सिफारिश- रिपोर्ट के दूसरे खंड में प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप दिया गया है। समिति ने मध्यप्रदेश में प्रचलित कानूनों और नियमों को ध्यान में रखते हुए विधेयक का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित विधेयक में चार भाग, 404 धाराएं और सात अनुसूचियां शामिल हैं। रिपोर्ट के तीसरे खंड में जन-परामर्श का विस्तृत विवरण दिया गया है। समिति ने जिला स्तर, राज्य स्तर और वेबसाइट के माध्यम से व्यापक सुझाव आमंत्रित किए थे। इस प्रक्रिया में 9.58 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनका प्रश्नवार, लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण रिपोर्ट में शामिल किया गया है। समिति ने अपनी अनुशंसाओं में अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश भी की है। अब सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लेगी।

कांग्रेस ने राजनीतिक दल के नाते स्पष्ट बात नहीं की

सीएम डॉ यादव ने कहा कि मुस्लिम, हिन्दू, ईसाई समाज ने अपने-अपने स्तर पर बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए। प्रदेश स्तर के राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस ने अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा है। यह कांग्रेस के दोहरे रवैया अपनाने की ओर इंगित करता है।

पीथमपुर में प्रॉपर्टी ब्रोकर ने सल्फास खाकर जान दी

पीथमपुर (नप्र)। पीथमपुर के घाटाबिल्लोद क्षेत्र में कर्ज की वसूली न होने और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर प्रॉपर्टी ब्रोकर ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। घाटाबिल्लोद के मूल निवासी मनोज मंडलोई ने सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है। मंगलवार को शुरुआती जांच के दौरान मृतक मनोज मंडलोई की जेब से मिले सुसाइड नोट में क्षेत्र के दो प्रभावशाली व्यक्तियों, उमेश गुप्ता पूर्व बीजेपी जिला महामंत्री और प्रोपर्टी व्यवसायी राम खंडेलवाल का स्पष्ट रूप से नाम लिखा हुआ है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस सुसाइड नोट में करीब साढ़े सात करोड़ रुपए के लेनदेन के विवाद का उल्लेख किया गया है।